तिब्बत देश

हु जिंताओ का भारत में तिब्बती विरोध उचित

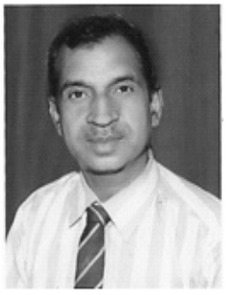

नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन के समय चीन के राष्ट्रपति हु जिंताओ का भारत में रह रहे तिब्बतियों तथा सभी तिब्बत मित्रों द्वारा भारी विरोध हमेशा याद किया जाएगा। ब्रिक्स में चूँकि ब्राजिल, रूस, इंडिया अर्थात भारत, चीन एवं साउथ अफ्रीका शामिल हैं, इसलिए यह सम्मेलन एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आयोजन था। यह ऐसा अवसर था, जहाँ तिब्बती एवं तिब्बत समर्थक चीन द्वारा तिब्बत में की जा रही हिंसा, क्रूरता तथा बर्बादी की ओर पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित कर सकते थे। हु जिंताओ का भारत–आगमन ही उनके रोष को बढ़ाने वाला था। वर्ष 1959 में चीन ने पूरी तरह तिब्बत पर अपना अवैध कब्जा कर लिया था। उस परिस्थिति में तिब्बतियों ने अपने धर्मगुरू परमपावन दलाई लामा के कुशल नेतृत्व में तिब्बत से भागकर भारत में रहने का निर्णय लिया। भारत सरकार ने भी उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान किया। तब से उन्हें सभी जरूरी सुविधायें भारत में उपलब्ध कराई जा रही हैं। हु जिंताओ उसी भारत में आएँ तो उन्हें तिब्बतियों के विरोध–प्रदर्शन का सामना करना ही पड़ेगा। प्रदर्शनकारियों का मकसद था विश्व जनमत चीन पर दबाव डाले और तिब्बत में चीन सरकार द्वारा जारी हिंसा बंद हो।

चीनी राष्ट्रपति हु जिंताओ के खिलाफ जारी विरोध ने लोगों का ध्यान तब ज्यादा खींचा, जब तिब्बती युवक जैम्फेल येशी ने 26 मार्च 2012 को आत्मदाह कर लिया। अन्य प्रदर्शनकारियों के समान उनकी भी मांग थी कि तिब्बत आजाद हो तथा परमपावन दलाईलामा ससम्मान तिब्बत वापस चलें। विरोध –प्रदर्शन का आयोजन तिब्बतन यूथ कांग्रेस द्वारा नई दिल्ली में जंतर–मंतर पर किया गया था, जिसमें पूरे भारत से तिब्बती स्वतंत्रता सेनानी जुटे थे। जैम्फेल येशी द्वारा आत्मदाह की घटना से सब स्तब्ध रह गए।

तिब्बत में जारी चीनी दमन के कारण लगातार तिब्बती भागकर भारत आ रहे हैं। पूर्वी तिब्बत के खाम तावू के मूल निवासी जैम्फेल येशी भी अपनी माँ और परिजनों को वहीं छोड़कर 2006 में भारत आ गए थे। तिब्बत में उन्होंने अपनी आँखों से चीनी आतंक को देखा था। भारत में रहते हुए उन्होंने तिब्बतियों में स्वतंत्र होने की छटपटाहट देखी। विश्व का ध्यान तिब्बत में जारी चीनी क्रूरता के प्रति खींचने के लिए दर्जनों बौद्ध भिक्षु–भिक्षुणी तथा अन्य लोग गत कुछ माह में ही आत्मदाह कर चुके हैं। यह क्रम अब भी जारी है। जैम्फेल येशी ने भी इसी रास्ते को चुना। चीन सरकार को समझना चाहिए कि इस प्रकार के कदम सार्थक संवाद के मार्ग बंद होने के कारण ही उठाए जा रहे हैं।

परमपावन दलाई लामा जी भगवान् बुद्ध और महात्मा गांधी के बताए सत्य–अहिंसा एवं मानवकल्याण के दर्शन को अपनाए हुए हैं। यद्यपि युवापीढ़ी चीन सरकार द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न का जबाव हिंसक तरीके से देने के पक्ष में है, फिर भी दलाई लामा जी युवा पीढ़ी को अनुशासित, मर्यादित एवं अहिंसक बनाए हुए हैं। चीन सरकार को चाहिए कि परमपावन दलाई लामा जी के साथ सार्थक संवाद करके मामले को यथाशीघ्र सुलझाए।

दलाई लामा जी चीन से सिर्फ वास्तविक स्वायत्तता की मांग कर चुके हैं, जबकि आंदोलनकारी पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी लेने को तैयार नहीं हैं। दलाई लामा जी के मतानुसार चीन की सरकार तिब्बत के संबंध में अन्य सभी विषय तिब्बत की सरकार को सौंप दे तथा ''प्रतिरक्षा'' एवं ''विदेशी मामले'' अपने पास रख ले। तिब्बत इस प्रकार चीन का अभिन्न अंग भी बना रहेगा और स्वायत्त भी रहेगा। लेकिन चीन की सरकार तिब्बत को वास्तविक स्वायत्तता देने को भी तैयार नहीं है। इसके विपरीत वह तिब्बत के इतिहास, संस्कृति, गौरव, पर्यावरण, अध्यात्म एवं प्राकृतिक संसाधन को सुनियोजित तरीके से बर्बाद और विकृत कर रही है।

विश्व समुदाय को चाहिए कि तिब्बत के समर्थन में खुलकर सामने आए। भारत को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तिब्बत के पक्ष में माहौल बनाना चाहिए। भारत एवं चीन के बीच मधुर संबंधों के लिए पूर्व की भांति भारत एवं चीन के बीच तिब्बत का बफर स्टेट (मध्यस्थ राज्य) होना जरूरी है। आज भी भारत में भारत–तिब्बत सीमा पुलिस है, जो कि इस तथ्य का प्रमाण है कि इतिहास के अनुसार कभी भी भारत के साथ चीन की सीमा नहीं मिलती थी। जैसे ही 1959 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया, भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। शीघ्र ही 1962 में चीन ने भारत पर हमला करके इसकी सैकड़ों वर्गमील जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। वह अब भी अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम तथा जम्मू–कश्मीर समेत भारत के अन्य हिमालयी प्रांतों पर अपना आधिपत्य जमाने के शड्यंत्र में मशगूल है।

हमें समझना होगा कि तिब्बतियों द्वारा दुर्भाग्यपूर्ण आत्मदाह केवल तिब्बत की आजादी के लिए ही नहीं है क्योंकि ''स्वतंत्र तिब्बत और सुरक्षित भारत'' एक ऐतिहासिक यथार्थ है। भारत में जारी तस्करी, अलगाववाद, आतंकवाद, हिंसा, बेरोजगारी तथा नकली नोटों में चीन की संलिप्तता बार–बार सामने आई है। भारत विरोधी ताकतों को ताकत चीन से मिल रही है। इसलिए तथाकथित ''हिन्दी–चीनी भाई–भाई'' के खोखले नारे में फिर से उलझने के बजाय भारत सरकार चीनी कब्जे से अपनी खोई जमीन मुक्त कराए तथा तिब्बत की आजादी का मार्ग प्रशस्त करे।

प्रो. श्यामनाथ मिश्र

पत्रकार एवं अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खेतड़ी (राज.)

चीन में तिब्बती किशोरी भिक्षुणी ने खुद को आग लगाई

तिब्बत की आज़ादी के समर्थक सबसे बड़े निर्वासित संगठन तिब्बती युवा कांग्रेस (टीवाईसी) ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के सामने तिब्बती नए साल के पहले दिन (लोसार) 22 फरवरी से आमरण अनशन शुरू किया है।

(गार्जियन डॉट सीओ डॉट यूके, 12 फरवरी)

तिब्बती इलाकों में चीनी प्रशासन की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की नवीनतम घटना में पश्चिमी चीन में एक 18 वर्षीय तिब्बती भिक्षुणी ने आत्मदाह का प्रयास किया है। एक तिब्बत आंदोलनकारी समूह ने यह जानकारी दी है।

फ्री तिब्बत नामक संगठन ने एक बयान में कहा है कि इस भिक्षुणी ने शनिवार को खुद को आग लगा ली और ऐसा माना जा रहा है कि उनकी जान बच गई है। तेनजिन छोजिन नाम की यह भिक्षुणी सिचुआन प्रांत के अबा प्रशासनिक क्षेत्र में स्थित ममाए ननरी (मठ) से जुड़ी हैं। संगठन का कहना है कि छोजिन ने मठ के पास स्थित एक चौराहे पर खुद को आग लगाने से पहले चीन सरकार के खिलाफ नारे लगाए। बयान में कहा गया है, "इसके बाद तत्काल वहां पुलिस और सेना के जवान पहुंच गए और उन्हें उठाकर ले गए। सैनिकों ने ननरी की घेराबंदी कर ली और उसे पूरी तरह से सील कर दिया गया है।"

पिछले एक साल में कम से कम 18 भिक्षु, भिक्षुणियां और आम तिब्बती खुद को आग लगा चुके हैं और 'फ्री तिब्बत' का कहना है कि इनमें कम से कम 12 लोग अपनी जान गवां चुके हैं। आंदोलनकारी संगठन का कहना है कि आत्मदाह करने वाले ऐसा चीन की नीतियों के खिलाफ कर रहे हैं और वे तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को वापस लाने की मांग भी कर रहे हैं जो साल 1959 में चीनी शासन के खिलाफ हुई जनक्रांति के विफल हो जाने के बाद हिमालयी क्षेत्र से होते हुए भारत चले गए थे। इसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय तिब्बत अभियान (आईसीटी) द्वारा जारी बयान में भारत में रहने वाले दो निर्वासित तिब्बती भिक्षुओं लोसांग येशी और कानयाग सेरिंग के हवाले से बताया गया है कि छोजिन अपने मां–बाप की चार संतानों में सबसे बड़ी हैं और वह एक अच्छी विद्यार्थी हैं। दलाई लामा के प्रति प्रखर श्रद्धा दिखाने का ममाए मठ का इतिहास रहा है। आईसीटी के बयान में बताया गया है कि गत अक्टूबर माह में इसी ननरी की एक 20 साल की भिक्षुणी की आत्मदाह से मौत हो गई थी। इसी ननरी के भिक्षुणियों के एक समूह ने मार्च, 2008 में दलाई लामा की तस्वीरें हाथ में लेकर एक विरोध मार्च निकाला था जिसके बाद बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई थीं और कई भिक्षुणियों को जेल की सजा सुना दी गई थी।

चीन सरकार आत्मदाह की इन घटनाओं की आलोचना कर रही है और उसका कहना है कि तिब्बती इलाकों में हिंसा के अचानक बढ़ जाने की वजह (जिनमें तिब्बती विरोध प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुए कई हिंसक टकराव भी शामिल हैं) बाहरी ताकतों का उकसावा है जो तिब्बत को चीन से अलग करना चाहती हैं। चीन एक दशक से भी ज्यादा समय से यह आरोप लगाते हुए दलाई लामा को बदनाम करता रहा है कि वे हिमालयी क्षेत्र तिब्बत को शेष चीन से अलग करने का अभियान चला रहे हैं। जबकि दलाई लामा का कहना है कि वह केवल तिब्बत के लिए ज्यादा स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। साल 2008 के बाद पिछले कुछ महीने इस इलाके के लिए सबसे हिंसक दौर साबित हुए हैं। साल 2008 में तिब्बत की राजधानी ल्हासा में भयानक दंगे हुए थे जो आसपास के प्रांतों तक फैल गए थे। अशांति से निपटने के लिए चीन ने तिब्बती इलाकों में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की है और करीब एक साल से तिब्बती इलाके को विदेशियों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। चीन का दावा है कि शताब्दियों से तिब्बत पर उसका शासन रहा है, लेकिन तिब्बतियों का कहना है कि यह इलाका ज्यादातर समय आज़ाद रहा है। यह धारणा मजबूत हो रही है कि चीन के दूसरे इलाकों से आने प्रवासियों की वजह से तिब्बती आर्थिक रूप से हाशिए पर जा रहे हैं, इस वजह से सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रतिबंधों के खिलाफ गुस्सा और बढ़ता जा रहा है।

रेबगोंग में नए साल का उत्सव नहीं मना, आत्मदाह करने वालों को श्रद्धांजलि

(तिब्बत डॉट नेट, 5 फरवरी, धर्मशाला)

वैसे तो तिब्बतियों के लिए 23 जनवरी को चीनी नए साल की शुरुआत होती है, लेकिन रेबगोंग के तिब्बतियों ने तिब्बत में आज़ादी और परमपावन दलाई लामा की अपनी मातृभूमि में वापस बुलाने की मांग करते हुए आत्मदाह कर शहीद हो जाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए चीनी नए साल का उत्सव नहीं मनाया और इन शहीदों के लिए प्रार्थनाएं कीं। रेबगोंग से मिली खबरों के मुताबिक इस समूचे इलाके में कोई उत्सव नहीं मनाया गया और नए साल के पहले, तीसरे, पांचवें और नौवें दिन पर आयोजित होने वाले सिर्फ पारंपरिक रिवाजों का आयोजन किया गया। उत्सवों पर होने वाले खर्च की जगह लोगों ने पैसा घी के दिए जलाने और प्रार्थना समारोहों आदि में लगाए। नए साल के पहले दिन से ही परिवारों का हर सदस्य प्रार्थनाएं कर रहा है। सभी लोग नौवें दिन पर आयोजित होने वाले प्रार्थना सभा में शामिल हुए और घी के दिए जलाए। नए साल के समारोह के अंतिम दिन जो खर्च होता था उसका पैसा बचाकर रोंगबो में पंद्रहवें दिन एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया और इसमें तिब्बत के लिए आत्मदाह कर शहीद हो जाने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थनाएं की गईं।

तीन तिब्बतियों ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर आमरण अनशन भुरू किया

(फायूल डॉट कॉम, धर्मशाला, 23 फरवरी)

तिब्बत की आज़ादी के समर्थक सबसे बड़े निर्वासित संगठन तिब्बती युवा कांग्रेस (टीवाईसी) ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के सामने तिब्बती नए साल के पहले दिन (लोसार) 22 फरवरी से आमरण अनशन शुरू किया है। तीन तिब्बतियों ने 'तिब्बत के भीतर रहने वाले तिब्बतियों के प्रति एकजुटता दिखाने और आज़ादी की अपनी मांग को मजबूत करने' के लिए 'तिब्बत के लिए आमरण अनशन' शुरू किया है। इनमें एक उच्च स्तर के पुनर्जन्म लिए लामा भी शामिल हैं। आमरण अनशन पर बैठे तीन तिब्बतियों में 32 साल के प्रख्यात राजनीतिक एवं साहित्यिक आंदोलनकारी परमश्रेष्ठ 11वें शिंगजा रिनपोछे, 59 साल के तिब्बती–अमेरिकी दोरजी ग्यालपो और लंबे समय से सक्रिय रहे तिब्बती युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता 39 साल के येशी तेनजिंग शामिल हैं। ये तीनों सीधे संयुक्त राष्ट्र से निवेदन कर रहे हैं कि वह तत्काल तिब्बत में एक तथ्यान्वेषी दल भेजे और चीन पर इस बात के लिए दबाव बनाए कि वह तिब्बत में अघोषित सैनिक शासन खत्म करे, अंतरराष्ट्रीय मीडिया को तिब्बत के भीतर जाने की इजाजत दे, गेदुन छोक्यी निमा एवं टुल्कू तेनजिन डेलेक सहित सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करे और तिब्बत में तथाकथित 'देशभक्ति पुनर्शिक्षा' अभियान को रोके।

तिब्बती नेताओं ने कहा, "हम दुनिया भर के नेताओं और सरकारों से भी यह निवेदन करते हैं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें और तिब्बत में जारी नरसंहार को रोकने के लिए सीधे चीनी नेताओं से बात करें।"

साल 2009 में तापे के आत्मदाह करने के बाद अब तक 23 तिब्बती अपने आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को वापस बुलाने और तिब्बत में आज़ादी की मांग को लेकर आत्मदाह का प्रयास कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र इमारत के सामने अनशन की शुरुआत करते हुए टीवाईसी ने कहा कि आत्मदाह के ये 'निडर कदम' चीन और दुनिया को लगातार यह याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि 'तिब्बती लोग आज़ादी की मांग' कर रहे हैं। टीवाईसी ने कहा, "दुनिया लगातार तिब्बत की आज़ादी के आंदोलन के बारे में चीन सरकार की झूठी तस्वीर पर आंखे मूदे भरोसा करने की भारी गलती नहीं कर सकती। जिसे कि शर्मनाक तरीके से चीन ने एक नस्लीय टकराव या धार्मिक आज़ादी के लिए संघर्ष के सीमित रूप में पेश किया है। जब तक चीन तिब्बत पर अवैध तरीके से कब्जा बरकरार रखेगा तिब्बती जनता का अवर्णनीय दमन न केवल जारी रहेगा बल्कि तिब्बत की आज़ादी की मांग भी बरकरार रहेगी और यह प्रतिरोध लगातार बढ़ता और मजबूत होता जाएगा।"

आत्मदाह की लहर हाल के हफ्तों में तिब्बत में तेजी से बढ़ी है और पिछले हफ्ते ही कम से कम तीन तिब्बतियों ने खुद को आग लगाई है। टीवाईसी का कहना है कि, "इन शहीदों का बलिदान यह साबित करता है कि तिब्बती लोगों के दिल एवं दिमाग में जगह बनाने के अपने प्रयास में चीन लगातार असफल रहा है।" टीवाईसी का कहना है कि, "चीन को अब यह वास्तविकता समझ जानी चाहिए वह तिब्बती लोगों की अदम्य इच्छा पर कभी भी विजय नहीं पा सकता जो कि एकसाथ खड़े हैं और एक दिन बर्बर कम्युनिस्ट चीन सरकार के राज को खत्म कर देंगे।"

आमरण अनशन पर बैठे तीनों तिब्बतियों ने संयुक्त राष्ट्र और दुनिया के नेताओं से आह्वान किया है कि, "वह तिब्बत में दमन का शिकार हो रहे तिब्बतियों की मांग पर ध्यान दें।" संगठन द्वारा जारी बयान में कहा गया है, "यदि आप तिब्बत के भीतर जल रही लपटों को बुझाने के लिए तत्काल कार्रवाई नहीं करेंगे तो तिब्बती लोगों की हर मौत की जवाबदेही आप की होगी।" निर्वासित तिब्बती नेता और मानवाधिकार संगठनों ने आशंका जताई है कि आगे और भी खून–खराबा और आत्मदाह की घटनाएं होंगी क्योंकि तिब्बत के कई हिस्सों में लगातार अघोषित रूप से सैन्य शासन लागू है और चीनी सुरक्षा बलों ने हाल के हफ्तों में कई निहत्थे तिब्बती प्रदर्शनकारियों को गोली मारकर शहीद कर दिया है।

तिब्बत की 'तालाबंदी'

(नई दिल्ली, 16 फरवरी, रायटर्स)

साल 2008 में घातक विरोध प्रदर्शनों के बाद से ही तिब्बतियों के अधिकारों को लगातार कम किया जा रहा है। सिपाहियों, जासूसों और जगह–जगह जांच बिंदुओं की वजह से चीन के भीतर का तिब्बती इलाका बंद किले में तब्दील हो चुका है। निर्वासित तिब्बती प्रधानमंत्री ने यह बात कही। लोबसांग सांगे ने रायटर्स को दिए इंटरव्यू में आज कहा कि निर्वासित तिब्बती नेताओं और चीन के बीच पिछले चार साल में रिश्ते खराब हुए हैं क्योंकि चीन सरकार ने तिब्बती दूतों के साथ वार्ता को टाल दिया है। चीन के तिब्बती इलाकों में साल 2008 में हुए दंगों में कम से कम 19 लोग मारे गए थे जिससे तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को मजबूर होकर इस इलाके के जीवन को 'धरती पर नर्क' की संज्ञा देनी पड़ी थी। सांगे ने बताया कि चीन ने तथाकथित तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र पर अपनी पकड़ और सख्त कर दी है, इस इलाके में सैनिकों और गैर तिब्बती चीनी नागरिकों की बाढ़ सी आ गई है और स्थानीय लोगों की नौकरी की संभावनाओं एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी को सीमित कर दिया गया है। दूसरी तरफ, चीन यहां होने वाली मौतों को आतंकवाद की कार्रवाई बता रहा है और उसने आरोप लगाया है कि भारत में निर्वासन में रह रहे दलाई लामा इस अशांति को बढ़ावा दे रहे हैं। सांगे ने कहा, "जो कुछ हो रहा है वह वास्तव में तिब्बत की तालाबंदी जैसा है और यह काफी चिंताजनक है। वे वास्तव में यह नहीं चाहते कि

"आप को यह दिखेगा कि तिब्बत में ज्यादा से ज्यादा चीनी पहुंच रहे हैं, वे तिब्बतियों की ज्यादा से ज्यादा नौकरियां छीन रहे हैं, प्रशासन में उनकी ज्यादा भागीदारी है, सैनिकों की संख्या बढ़ रही और तिब्बतियों के प्रति भेदभाव बढ़ता जा रहा है।"

आने वाला तिब्बती नया साल अशांत हिमालयी क्षेत्र में और खून–खराबा लेकर आने वाला है।

बाहरी दुनिया यह जाने कि तिब्बत में क्या हो रहा है।" साल 1950 में कम्युनिस्ट शासन के सैनिकों के तिब्बत में मार्च करने के बाद से ही इस पर चीन का शासन है। चीन ने इस आलोचना को खारिज किया है कि वह तिब्बती संस्कृति और विश्वास का क्षरण कर रहा है। चीन का कहना है कि उसके शासन से तिब्बत में दासप्रथा का अंत हुआ है और इस पिछड़े इलाके का काफी विकास हुआ है। चीन के शासन के खिलाफ साल 1959 में हुई तिब्बतियों की जनक्रांति विफल रहने पर दलाई लामा निर्वासित होकर भारत चले आए। सांगे ने कहा, "आप को यह दिखेगा कि तिब्बत में ज्यादा से ज्यादा चीनी पहुंच रहे हैं, वे तिब्बतियों की ज्यादा से ज्यादा नौकरियां छीन रहे हैं, प्रशासन में उनकी ज्यादा भागीदारी है, सैनिकों की संख्या बढ़ रही और तिब्बतियों के प्रति भेदभाव बढ़ता जा रहा है।"

सैकड़ों तिब्बतियों को हिरासत में लेकर राजनीतिक 'पुनर्शिक्षा' के लिए मजबूर किया गया

(रायटर्स, 17 फरवरी)

"किसी न किसी बहाने चीनी सुरक्षा बल तिब्बतियों पर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और चाहे उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उन्हें प्रताड़ित किया जाए या उनकी हत्या कर दी जाए दुनिया को इसकी जानकारी नहीं हो पाएगी।

न्यूयॉर्क स्थित संगठन ह्यूमन राइट्स वाच का कहना है कि उसके मुताबिक 1970 के दशक के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि अधिकारियों ने इतनी बड़ी संख्या में तिब्बती आम लोगों को पकड़ा है और ऐसा लगता है कि चीन अपने तिब्बती इलाकों में अशांति को लेकर खीजा हुआ है। चीन ने करीब 7,000 तिब्बतियों को इस बात की इजाजत दी थी कि वे भारत के बिहार राज्य में 31 दिसंबर से 10 जनवरी के बीच होने वाले परमपावन दलाई लामा के द्वारा प्रवचन सत्र में हिस्सा लें। इसे देखकर ऐसा लगता था कि चीन ने तिब्बतियों के प्रति अपनी नीति को नरम बना लिया है। लेकिन संगठन के मुताबिक, "पूर्वी तिब्बत के इलाकों में फैली अशांति और इस आशंका से कि यह ल्हासा के अन्य इलाकों में भी फैल सकता है, चीन ने अपनी नीतियों में बदलाव कर दिया।" संगठन ने शुक्रवार को ई–मेल से भेजे एक बयान में तिब्बत की राजधानी ल्हासा के संदर्भ में यह बात कही।

गौरतलब है कि पिछले साल मार्च से अब तक चीनी शासन के विरोधस्वरूप कम से कम 15 तिब्बतियों की मौत हो जाने की खबरें हैं। आत्मदाह की ज्यादातर घटनाएं चीन के सिचुआन और गांसू प्रांत के तिब्बती इलाकों में हुई हैं और इनके मुकाबले तिब्बत के भीतर कम घटनाएं हुई हैं। तिब्बत की आवाज़ बुलंद करने वाले संगठन का कहना है कि सिचुआन प्रांत में जनवरी माह में हुए विरोध प्रदर्शनों में सुरक्षा बलों की गोलीबारी से कम से कम सात तिब्बती मारे गए हैं और दर्जनों अन्य घायल हो गए हैं। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक पुलिस ने उस 'भीड़' से आत्मरक्षार्थ गोली चलाई जिसने पुलिस थाने पर हमला कर दिया था। जबकि आंदोलनकारियों का कहना है कि चीन ने तिब्बतियों की धार्मिक आज़ादी एवं संस्कृति का हिंसक रूप से दमन किया है। तिब्बत पश्चिमी चीन का एक विस्तृत, सीमांत और काफी हद तक पहाड़ी इलाका है जो कि साल 1950 से ही चीन के नियंत्रण में रहा है। चीन ने धार्मिक आज़ादी को कुचलने के आरोपों का खंडन किया है और उसका कहना है कि उसके शासन से तिब्बत में जरूरी विकास हुआ है। मानवाधिकार संगठन का कहना है कि जिन तिब्बतियों को हिरासत में लिया गया है वे वैध पासपोर्ट के साथ चीन के भीतर और बाहर यात्रा कर रहे थे। उन्होंने कहा, "तिब्बतियों को धार्मिक शिक्षण में शामिल होने से रोकने के लिए कोई कानून नहीं है और विदेश से लौटने वाले जिन लोगों को पुनर्शिक्षा दिया जा रहा है उन्होंने कोई अवैध दस्तावेज रखने या बिना इजाजत के चीनी सीमा पार करने का कोई अपराध नहीं किया है। ऐसी कोई खबर नहीं है कि बिहार में दलाई लामा के शिक्षण कार्यक्रम से लौटने वाले करीब 700 चीनी नागरिकों में से भी किसी को गिरफ्तार किया गया है। इसका मतलब यह है कि लोगों को सिर्फ नस्ल के आधार पर हिरासत में लिया गया है।" इस बारे में तिब्बत सरकार के अधिकारियों से हमने बात करने की कोशिश की लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। मानवाधिकार संगठन का कहना है कि चीन के तिब्बती इलाके में तिब्बती नव वर्ष (22 फरवरी) से पहले भारी सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। साल 1959 में चीनी शासन के खिलाफ हुई जनक्रांति के विफल हो जाने के बाद दलाई लामा निर्वासित होकर भारत चले गए थे।

तिब्बत में 'लोसार' मनाने के लिए लोगों को मजबूर किया गया

(फायूल डॉट कॉम, धर्मशाला, 22 फरवरी)

सल 2009 और उसके बाद के सालों में तिब्बत के कई हिस्सों में जैसी रणनीति अपनाई गई थी उसी को दोहराते हुए तिब्बत की राजधानी ल्हासा में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों ने 'लोसार' (तिब्बती नव वर्ष 22 से 24 फरवरी) न मनाने के लोकप्रिय आह्वान के खिलाफ सख्त चेतावनी जारी की है। गौरतलब है कि तिब्बती नागरिकों और निर्वासित तिब्बती नेताओं ने भी यह आह्वान किया है कि तिब्बत में जारी आत्मदाह की लहर को देखते हुए इस साल लोसार का उत्सव न मनाया जाए। दलाई लामा को वापस तिब्बत बुलाने और तिब्बत की आज़ादी की मांग को लेकर 23 तिब्बती आत्मदाह का प्रयास कर चुके हैं।

कई निर्वासित तिब्बती सूत्रों ने बताया था कि ल्हासा में सरकारी अधिकारियों ने आदेश जारी कर कहा है कि तिब्बती अधिकारी एवं आम जनता इस साल लोसार के अवसर पर होने वाले परंपरागत नृत्य एवं गीत की तैयारी कर ले। जिन लोगों ने इस तरह के अनिर्वाय उत्सव में शामिल होने से इनकार किया है उनको गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई है। तिब्बतियों

को लोसार उत्सव में शामिल होने के लिए मनाने के लिए फुसलाने के प्रयास के तहत सरकारी अधिकारियों ने अस्थायी रूप से कुछ तिब्बतियों को जेल से रिहा कर दिया है जिन्हें भारत एवं नेपाल से तीर्थयात्रा पूरी कर लौटते समय मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया था। सूत्रों ने फायूल को बताया कि अज्ञात स्थानों पर 'देशभक्ति पुनर्शिक्षा' के लिए मजबूर किए जा रहे इन तिब्बतियों को लोसार के बाद फिर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ल्हासा में रहने वाले एक तिब्बती ने फायूल को बताया, "ल्हासा में चीनी अधिकारियों ने लोसार का उत्सव मनाने के लिए कुछ तिब्बती कैदियों को रिहा किया है लेकिन उनसे कहा गया कि नए साल का उत्सव मनाने के बाद उन्हें फिर से जेल में वापस आना पड़ेगा।"

समूचे तिब्बत में साल 2008 में हुए व्यापक जनक्रांति के बाद साल 2009 में भी चीनी अधिकारियों ने लोसार उत्सवों के बहिष्कार के खिलाफ लोगों को जबरन उत्सव मनाने को मजबूर किया था। इस साल तिब्बत की कम्युनिस्ट पार्टी ने 37,000 गरीब परिवारों को 120 डॉलर (करीब 6000 रुपए) का एक गिफ्ट बाउचर भी दिया है जिससे वे नए साल की छुट्टियों के दौरान शॉपिंग कर सकें। पिछले महीने फायूल ने यह खबर दी थी कि चीन सरकार लोसार उत्सव मनाने के लिए तिब्बतियों को उपहार एवं पैसे का घूस दे रही है। अब तिब्बती सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि हर परिवार को 500 युआन या प्रत्येक व्यक्ति के लिए 200 युआन का घूस दिया गया है। इस सूत्र ने बताया, "तिब्बत में रहने वाले 99 फीसदी तिब्बती इस साल लोसार का उत्सव नहीं मनाएंगे, लेकिन बहुत से लोग डरे हुए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यदि वे उत्सव नहीं मनाएंगे तो उनके लिए यह भारी पड़ेगा।" तिब्बत के भीतर पूरी से नाकाबंदी वाले नाबा क्षेत्र में संपर्क रखने वाले एक और निर्वासित तिब्बती ने फायूल को बताया कि तिब्बती 'आगामी लोसार उत्सवों को न मनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।' कीर्ति मठ के निर्वासित केंद्र के भिक्षु कानयाग सेरिंग ने बताया, "तिब्बत में रहने वाले तिब्बती इस साल लोसार का उत्सव न मनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं क्योंकि हम इसे काला साल मान रहे हैं। जब किसी परिवार में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उस साल को काला साल माना जाता है।" यही नहीं इसके बाद दुनिया भर के तिब्बतियों ने आज लोसार के पहले दिन को अनशन एवं जागरूकता कार्यक्रमों के रूप में मनाया।

निर्वासित तिब्बतियों ने दी चेतावनी, चीन की सख्त कार्रवाई की योजना

(धर्मशाला, एसोसिएटेड प्रेस, 14 फरवरी)

आने वाला तिब्बती नया साल अशांत हिमालयी क्षेत्र में और खून–खराबा लेकर आने वाला है। निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रमुख ने मंगलवार को चेताया कि चीन ने सख्त कार्रवाई की तैयारी करते हुए समूचे तिब्बत इलाके को सील कर दिया है। तिब्बत की आज़ादी और परमपावन दलाई लामा की वापसी के लिए करीब दो दर्जन आत्मदाह (जिसमें ज्यादातर बौद्ध भिक्षु या भिक्षुणी हैं) का गवाह बन चुके तिब्बती इलाकों में संभावित विरोध प्रदर्शन पर सख्त कार्रवाई के लिहाज से चीन हजारों की संख्या में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर रहा है। एसोसिएटेड प्रेस के साथ एक इंटरव्यू में निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रधानमंत्री लोबसांग सांगे ने कहा, "उन्होंने समूचे तिब्बत को सील कर दिया है।" उन्होने कहा कि 22 फरवरी को तिब्बती नए साल के उत्सव और साल 1959 की विफल जनक्रांति के दस मार्च को आने वाली वर्षगांठ के अवसर पर तिब्बतियों के सड़कों पर उतर जाने की संभावना है। लेकिन यह इलाका बाहरी लोगों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है (विदेशी पर्यटकों से इलाका छोड़ने को कह दिया गया है और पश्चिमी देशों के पत्रकारों का प्रवेश तो सख्ती से वर्जित है) इसलिए वहां के वास्तविक हालात के बारे में जान पाना बिल्कुल असंभव जैसा हो गया है। धर्मशाला में जहां कि दलाई लामा एवं निर्वासित तिब्बती सरकार का केंद्र है, इस इंटरव्यू में लोबसांग सांगे ने कहा, "किसी न किसी बहाने चीनी सुरक्षा बल तिब्बतियों पर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और चाहे उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उन्हें प्रताड़ित किया जाए या उनकी हत्या कर दी जाए दुनिया को इसकी जानकारी नहीं हो पाएगी। दूसरी तरफ, चीनी प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ ने मंगलवार को तिब्बत पर चीनी नीतियों का बचाव करते हुए कहा कि सरकार परंपरागत संस्कृति और धार्मिक मान्यता की आज़ादी का सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि तिब्बत में चीन सरकार बड़े पैमाने पर निवेश कर रही है और आगे भी ऐसा करती रहेगी। गौरतलब है कि पश्चिमी चीन के तिब्बती इलाकों में हाल के महीनों में लगातार अशांति बढ़ती गई है। आत्मदाह की लहर सी शुरू हो गई है और लगातार विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला चल रहा है जिसमें कई बार खून–खराबा भी हुआ है। तिब्बती इलाकों में साल 2008 के बाद हिंसा का सबसे बुरा दौर चल रहा है और सबसे ज्यादा प्रभाव सिचुआन प्रांत में देखा गया है। तिब्बत से जो जानकारियां आ रही हैं वह भी आधी–अधूरी हैं। जिन लोगों ने आत्मदाह किया है वे जिंदा हैं या नहीं और विरोध प्रदर्शनों में क्या हो रहा है इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। लंदन स्थित तिब्बत के लिए अंतरराष्ट्रीय अभियान (आईसीटी) नामक संगठन ने बताया कि सोमवार को सिचुआन के अबा प्रशासनिक क्षेत्र के एक किशोर भिक्षु ने खुद को आग लगा ली। संगठन ने बताया कि इसके बाद चीनी सुरक्षा बलों ने इस भिक्षु की आग की लपटें बुझाने के साथ ही उसकी जमकर पिटाई भी की। उनकी हालत के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा।

"चीन के नेताओं, कृपया ध्यान दें। हम आपसे निवेदन करते हैं कि तिब्बत को वह दें जिसकी चीन जनवादी गणतंत्र का संविधान इजाजत देता है–स्वायत्तता।" रंगभेद विरोधी पूर्व आंदोलनकारी टुटु को अक्सर 'दक्षिण अफ्रीका की नैतिक आत्मा' माना जाता है।

इस मुलाकात के बाद डीपीपी ने तिब्बत में नवीनत घटनाओं पर तीन बिंदु का बयान जारी किया।

चीन का आरोप है कि बाहरी और चरमपंथी तत्व हिंसा को भड़काने और चीन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सांगे और अन्य तिब्बती नेताओं का कहना है कि आत्मदाह की बढ़ती घटनाओं से पता चलता है कि लगातार हताश होती तिब्बती जनसंख्या अपनी बात कह पाने में असमर्थ है जिसकी वजह से दूसरे रास्तों का सहारा ले रही है। सांगे ने कहा, "वहां लोग अनशन नहीं कर सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते और ज्ञापन नहीं दे सकते। इस तरह की दमनकारी नीतियों एवं कार्यों की वजह से तिब्बती हताशा के कगार पर पहुंच गए हैं।" उन्होंने कहा, "वे यह सोच रहें हैं कि शायद इस तरह के कार्यों से तिब्बती जनता की परेशानियों की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित होगा।" दूसरी तरफ, चीन का आरोप है कि निर्वासित तिब्बती सरकार तिब्बत को चीन से अलग करना चाहती है। हालांकि, निर्वासित तिब्बतियों और दलाई लामा का कहना है कि वे सिर्फ चीनी शासन के भीतर व्यापक स्वायत्तता की मांग ही कर रहे हैं। चीन ने साल 1950 में चीन पर कब्जा कर लिया था और उसका दावा है कि शताब्दियों से यह इलाका उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, जबकि तिब्बतियों का कहना है कि यह हिमालयी क्षेत्र शताब्दियों से पूरी तरह स्वतंत्र रहा है।

दलाई लामा, डेसमंड टुटु ने तिब्बत में चीनी दमन की भर्त्सना की

(वीओए, 10 फरवरी, नई दिल्ली)

दलाई लामा की निर्वासन से वापसी और तिब्बत की आज़ादी की मांग को लेकर 23 तिब्बती आत्मदाह कर चुके हैं।

तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने उत्तरी भारत के शहर धर्मशाला में दक्षिण अफ्रीका के आर्कबिशप डेसमंड टुटु की अगवानी की। टुटु ने इस अवसर पर चीन से भावप्रवण निवेदन किया कि वह तिब्बत के प्रति अपनी नीतियों में बदलाव लाए। दलाई लामा ने गुरुवार को अपने साथी नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित हस्ती आर्कबिशप डेसमंड टुटु से अनुरोध किया कि वह तिब्बती लोगों के लिए भी प्रार्थना करें। दलाई लामा ने कहा, "हम तिब्बती एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं और तिब्बती संस्कृति से मिली हमारी करुणा की नीति भी वास्तव में काफी चुनौतियों से गुजर रही है।" तिब्बती आध्यात्मिक नेता महीनों से तिब्बत में जारी दमन की बात कर रहे थे। निर्वासित तिब्बतियों का कहना है कि हाल के हफ्तों में तिब्बत में कम से कम छह शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हुए हैं। चीन सरकार ने एक तिब्बती की हत्या की बात स्वीकार की है जिसे वह 'दंगाई' कहती है और सरकार का कहना है कि 'विशेष रूप से प्रशिक्षित भीड़' द्वारा ये विरोध प्रदर्शन सुनियोजित तरीके से किए जा रहे हैं जो पुलिस के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल करते हैं।

तिब्बतियों का कहना है कि चीन ऐसी नीति अपना रहा है जिसके तहत तिब्बत में लगातार गैर तिब्बती चीनी प्रवासियों का बसना जारी है, जो अक्सर तिब्बतियों के प्रति भेदभाव करते हैं। वहां दलाई लामा की तस्वीर रखने पर रोक है और कई भिक्षुओं का कहना है कि यदि वे राष्ट्रवादी 'पुनर्शिक्षा कार्यक्रम' (जो उन्हें उनके परंपरागत संस्कृति से दूर कर रही है) में शामिल नहीं होते तो उन्हें सजा दी जाती है।

टुटु ने चीन से निवेदन किया है कि वह तिब्बत पर अपनी पकड़ को थोड़ा नरम करे। टुटु ने कहा, "चीन के नेताओं, कृपया ध्यान दें। हम आपसे निवेदन करते हैं कि तिब्बत को वह दें जिसकी चीन जनवादी गणतंत्र का संविधान इजाजत देता है–स्वायत्तता।" रंगभेद विरोधी पूर्व आंदोलनकारी टुटु को अक्सर 'दक्षिण अफ्रीका की नैतिक आत्मा' माना जाता है। खुद टुटु दलाई लामा को 'इस धरती का सबसे शांति प्रिय व्यक्ति' मानते हैं। उन्होंने चीन से आह्वान किया कि वह तिब्बती आध्यात्मिक नेता को उनकी मातृभूमि पर वापस जाने दे। उन्होंने कहा कि, "भगवान वह दिन जल्दी ही लाएगा, जब हम एक आज़ाद तिब्बत में प्रवेश करेंगे।" साल 1959 में चीन के खिलाफ जनक्रांति विफल हो जाने के बाद दलाई लामा अपने हजारों तिब्बती समर्थकों के साथ भारत चले आए थे। धर्मशाला स्थित निर्वासित तिब्बती प्रशासन के निर्वाचित प्रधानमंत्री लोबसांग सांगे ने कहा कि उन्हें डर है कि चीन का दमन और बढ़ेगा। पिछले एक साल में चीनी नीतियों के खिलाफ आत्मदाह कर लेने वाले 19 तिब्बतियों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस हफ्ते आयोजित कैंडल लाइट निगरानी कार्यक्रम के दौरान सांगे ने यह बात कही। सांगे ने कहा, "हमें ऐसी खबरें मिली हैं कि ऑटोमेटिक मशीन गन से लैस चीनी सुरक्षा बलों के सैकड़ों दल तिब्बत की तरफ बढ़ रहे हैं। अगले 22 फरवरी को तिब्बती नव वर्ष आ रहा है जिस पर बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा होगा, हमें आशंका है कि इस मौके पर कई तिब्बतियों को दुर्भाग्यपूर्ण अनुभवों का सामना करना पड़ सकता है।"

कई देशों के सांसदों ने तिब्बत में संयुक्त राष्ट्र से तथ्यान्वेषी दल भेजने का आह्वान किया

(धर्मशाला)

उत्तर–पूर्वी तिब्बत में चीनी सुरक्षा बलों द्वारा तिब्बतियों की हत्याएं और तिब्बत की पूरी तरह से नाकाबंदी की खबरों पर गहरी चिंता जताते हुए कई देशों के सांसदों ने मांग की है कि तिब्बत के हालात का जायजा लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र का तथ्यान्वेषी दल भेजा जाए। गत 31 जनवरी को जारी बयान में तिब्बत पर सांसदों के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क (आईएनपीएटी) ने कहा कि उन्हें इन खबरों पर गहरी चिंता है कि पिछले हफ्ते चीनी सुरक्षा बलों द्वारा की गई गोलीबारी में ड्रागो, कार्डजे और नाबा के जामथांग में कई तिब्बती मारे गए हैं। बयान में कहा गया है, "आईएनपीएटी का मानना

है कि तिब्बतियों द्वारा अभिव्यक्ति एवं सभा करने की आज़ादी की मांग को लेकर किए जा रहे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों पर चीनी प्रशासन द्वारा किया जा रहा बल प्रयोग उचित नहीं है। आईएनपीएटी को इस बात को लेकर गहरी चिंता है कि तिब्बतियों की गैरकानूनी तरीके से हत्याओं के ये मामले ऐसे दौर में हुए हैं जब साल 2009 से अब तक 17 तिब्बतियों ने विरोधस्वरूप आत्मदाह किए हैं और इनमें 12 लोगों को अपनी जान गवांनी पड़ी है। आईएनपीएटी इस बात की भर्त्सना करता है कि विभिन्न स्रोतों के मुताबिक तिब्बत में भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है और पत्रकारों एवं अन्य स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को तिब्बती इलाकों, खासकर सिचुआन प्रांत में नहीं जाने दिया जा रहा है। आईएनपीएटी चीनी प्रशासन से यह मांग करता है कि वे इस बात की पर्याप्त जानकारी दें कि पिछले साल 16 मार्च को वेन फुंसोक द्वारा आत्मदाह की पहली घटना के बाद हिरासत में लिए गए तिब्बतियों का क्या हाल है और उन्हें कहां रखा गया है। साथ ही संगठन धार्मिक संस्थाओं सहित अन्य जगहों पर लगाई गई सुरक्षा संबंधी सख्ती खत्म करने की भी मांग करता है।" संगठन ने अपने बयान में कहा है, "आईएनपीएटी इस बात का स्वागत करता है कि कई देशों के सांसदों ने तिब्बत में मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर अपनी चिंता जताई है, खासकर तिब्बतियों द्वारा विरोध में आत्मदाह की चेतावनीपूर्ण रूप से बढ़ती घटनाओं के बाद के हालात पर। तिब्बती जनता की आकांक्षा के साथ एकजुटता दिखाते हुए आईएनपीएटी ने तिब्बतियों से अनुरोध किया है कि वे आत्मदाह के द्वारा अपने कीमती जीवन का बलिदान न करें बल्कि अपनी सामूहिक आवाज़ और ताकत को बनाए रखते हुए चीनी प्रशासन से मिलने वाली चुनौतियों का मुकाबला करें। आईएनपीएटी चीनी प्रशासन से भी यह अनुरोध करता है कि वे मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त द्वारा चीन में एक तथ्यान्वेषी दल भेजने के हमारे अनुरोध पर मुस्तैदी से प्रतिक्रिया दिखाएं और यह सुनिश्चित करें कि इस प्रकार के दौरे में शामिल दल को तिब्बत के हालात का जायजा लेने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। आईएनपीएटी का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्च अधिकारी के इस तरह के दौरे से इस बात का स्वतंत्र तौर पर आकलन हो सकेगा कि साठ लाख तिब्बती किस तरह से मानवाधिकार संकट का सामना कर रहे हैं।" तिब्बत पर हुए पांचवें विश्व सांसद सम्मेलन (रोम, 18–19 नवंबर, साल 2009) में 33 देशों के 133 सांसदों ने हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन में 'तिब्बत पर रोम घोषणापत्र' स्वीकार किया गया था जिसके तहत तिब्बत पर सांसदों के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क (आईएनपीटी) का गठन हुआ था।

ताइवान के नेता ने तिब्बत में चीनी दमन की निंदा की

(फायूल डॉट कॉम, धर्मशाला, 24 फरवरी)

ताइवान में राष्ट्रपति के पूर्व उम्मीदवार और वहां की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी की नेता ने तिब्बत के हालात पर चिंता जताई है और राष्ट्रपति मा यिंग–जियो से भी अनुरोध किया है कि वह चीन सरकार तक अपनी चिंता पहुंचाएं। डेमाक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की अध्यक्ष साइ इंग वेन ने कहा है कि परमपावन दलाई लामा के तिब्बत धार्मिक फाउंडेशन के निदेशक दावा सेरिंग से बुधवार को मुलाकात में यह जानकर उनके दिल को काफी धक्का लगा कि तिब्बतियों द्वारा आत्मदाह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। दलाई लामा की निर्वासन से वापसी और तिब्बत की आज़ादी की मांग को लेकर 23 तिब्बती आत्मदाह कर चुके हैं। हाल में निहत्थे तिब्बती प्रदर्शनकारियों की हत्याओं के बाद तिब्बत के कई हिस्सों में एक तरह से अघोषित सैनिक शासन लागू है। ताइपेई टाइम्स के अनुसार साई ने इस बात को दुहराया कि डीपीपी तिब्बत के लोकतांत्रिक आंदोलन का पूरी तरह से समर्थन करती है और ताइवान में तिब्बतियों की भलाई के लिए काम करती रहेगी। पिछले माह हुए आम चुनाव में डीपीपी को कुओमिंगतांग (चीनी राष्ट्रवादी पार्टी) के मुकाबले हार का सामना करना पड़ा था। राष्ट्रपति मा ने यह संदेश दिया था कि वह चीन के साथ रिश्तों को बेहतर बनाकर देश में ज्यादा समृद्धि लाएंगे। इस मुलाकात के दौरान सेरिंग ने तिब्बती आध्यात्मिक नेता परमपावन दलाई लामा का एक पत्र सौंपा जिसमें उन्होंने ताइवान के लोकतांत्रिक विकास और राष्ट्रपति चुनावों में साई द्वारा किए गए प्रयासों के लिए उनकी तारीफ और कद्र की थी। खबरों के अनुसार दलाई लामा ने पत्र में साइ को अपने इस निर्णय के बारे में बताया था कि वह पिछले साल ही निर्वासित तिब्बती प्रशासन के राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया से खुद को अलग कर चुके हैं। 76 साल के तिब्बती नेता साल 2009 में टाइफून मोराकोट द्वारा हुए विनाश के बाद ताइवान की यात्रा पर गए थे। इस टाइफून के कहर से वहां कम से कम 650 लोग मारे गए थे। अपने लघु दौरे के दौरान दलाई लामा ने प्रार्थना सभाओं का नेतृत्व किया और दक्षिणी ताइवान के सबसे ज्यादा प्रभावित कुछ इलाकों में गए। चीन ने दलाई लामा के इस मानवीय दौरे की तत्काल आलोचना करते हुए कहा था कि निर्वासित तिब्बती नेता का ताइवान द्वारा मेजबानी करने का वह 'सख्त विरोध' करता है।

इस मुलाकात के बाद डीपीपी ने तिब्बत में नवीनत घटनाओं पर तीन बिंदु का बयान जारी किया। डीपीपी ने मा प्रशासन से आह्वान किया कि वह तिब्बती आंदोलनकारियों पर चीन के दमन की निंदा करे और

भारतीयों के लिए पर्वतीय रेल मार्ग काफी रोमांस से जुड़े होते हैं। कई फिल्मों में दार्जिलिंग के ट्वाय ट्रेन या शिमला, ऊटी की ओर जाने वाले रेलमार्गों को दर्शाया गया है। भारतीय रेल ने भी इस धारणा को बदलने के लिए कुछ नहीं किया है।

(1)

(2)

(10)

कैमरे की आंख

1 तिब्बती बौद्ध भिक्षुणी पालेन छोएत्सो, दाओफु (तिब्बती में ताउ) में आत्मदाह करते हु
2 बौद्ध भिक्षुणी तेनजिन छोजिन जिन्होंने तिब्बत के लिए अंतरराष्ट्रीय अभियान के मुता
3 शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने वाले एक तिब्बती की बुरी तरह पिटाई करते चीनी
4 सरथार में चीनी सुरक्षा बलों की गोली से मारे गए तिब्बती प्रदर्शनकारी का शव खींच
5 (बाएं से दाएं) संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क के सामने 22 फरवरी, 2012 को अनिश्चि
और येशी तेनजिंग।
6 नेपाल के काठमांडू स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के बाहर अपने स्मियर पुते चेहरे के
7 तिब्बत के भीतर रहने वाले तिब्बतियों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए धर्मशाला के सु
को संबोधित करते हुए निर्वासित तिब्बती संसद के स्पीकर पेनपा सेरिंग।
8 गत 29 फरवरी, 2012 को 45 दिन तक चली साइकिल रैली का नई दिल्ली में समा
9 ल्हासा में एक हिरासत केंद्र के बाहर इंतजार करते तिब्बती जहां भारत और नेपाल से
और उन्हें देशभक्तिपूर्ण पुनर्शिक्षा के लिए मजबूर किया गया।
10 पिछले महीने एक चुनाव सभा के दौरान ताइवान के डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की

(9)

(8)

♦ आंखों देखी

(3)

(4)

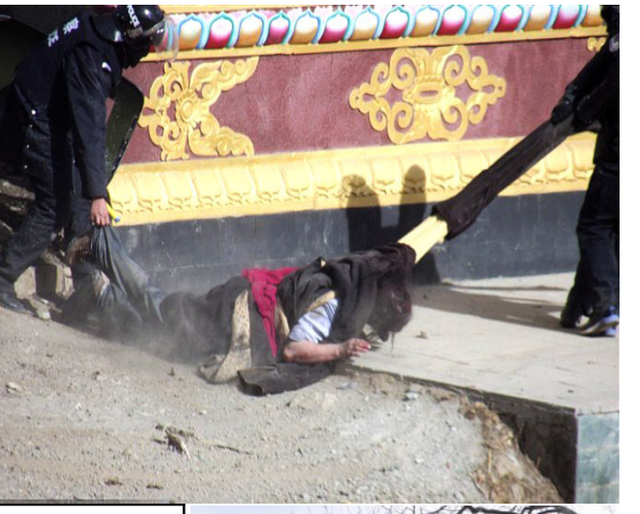

कैमरे की आंख से

में आत्मदाह करते हुए, यह तस्वीर 3 नवंबर, 2011 के एक वीडियो फिल्मांकन से ली गई है। य अभियान के मुताबिक खुद को आग लगा ली। (फ्री तिब्बत, एएफपी, गेट्टी इमेज)।
पिटाई करते चीनी सुरक्षा बल।
नकारी का शव खींचकर ले जाते चीनी सुरक्षा बल के जवान।
ी, 2012 को अनिश्चितकालीन अनशन करते हुए तीन तिब्बती दोरजी ग्यालपो, शिंगजा रिनपोछे

स्मियर पुते चेहरे के साथ प्रदर्शन करते तिब्बती विद्यार्थी।
हुए धर्मशाला के सुगला खांग में 22 फरवरी को लोसार के अवसर पर अनशन पर बैठे लोगों सेरिंग।
नई दिल्ली में समापन करते हुए तीन तिब्बती विद्यार्थी।
भारत और नेपाल से वापस लौट रहे तिब्बतियों को मनमाने तरीके से हिरासत में ले लिया गया

प्रोग्रेसिव पार्टी की राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी साइ इंग वेन। (फोटोः एपी)

(5)

(फोटो परिचय : ऊपर बाएं से घड़ी की दिशा में)

(7)

(6)

तिब्बत 1950 के दशक से ही चीन के नियंत्रण में है।

तिब्बत में मानवाधिकार की समस्याओं पर और चीन में लोकतांत्रिक आंदोलन के विकास पर ध्यान दे।

मानवाधिकारों और लोकतंत्र को डीपीपी के प्रमुख मूल्य मानते हुए पार्टी ने कहा कि इन मूल्यों को चीन के साथ बातचीत करने में ताइपेई सरकार को शामिल करना चाहिए। पार्टी ने ताइवान के लोकतंत्र में दलाई लामा के दिलचस्पी दिखाने पर भी कृतज्ञता जाहिर की।

तिब्बत में तनाव दूर करने में मदद को तैयार है भारतः कृष्णा

(पीटीआई, 8 फरवरी, बीजिंग)

चीन द्वारा यारलुंग (ब्रह्मपुत्र जो तिब्बत से होकर आती है) नदी पर बहुत ज्यादा बांध बनाने और इस नदी की जलधारा को मोड़ने का चीनी इरादा सोमवार को यहां होने वाले एक सम्मेलन का मुख्य विषय रहा।

तिब्बत मसले को चीन का एक आंतरिक मामला मानते हुए भारत ने बुधवार को कहा कि वह हाल में बढ़े तनाव को कम करने के लिए 'किसी भी तरह की मदद को तैयार है।' हालांकि, भारत ने तिब्बत में बौद्ध भिक्षुओं के आत्मदाह और उसके बाद जारी हिंसा को लेकर काफी सचेत रवैया अपनाया है। बुधवार को बीजिंग में चार वरिष्ठ चीनी मंत्रियों से गहन बातचीत करने के बाद विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा ने पत्रकारों से कहा कि वार्ता के दौरान तिब्बत मसले पर भी चर्चा हुई है। उन्होंने कहा, "हमने तिब्बत मसले पर भी चर्चा की है। भारत सरकार का पक्ष यह है कि तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र चीन जनवादी गणतंत्र (पीआरसी) का हिस्सा है जिसकी वजह से हम इसे चीन का आंतरिक मामला मान रहे हैं। इसलिए हमें इस मामले में बहुत सचेत रहना होगा और तनाव दूर करने के लिए यदि हम कोई मदद कर सकते हैं तो उसके लिए तैयार हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति आएगी।" कृष्णा से यह सवाल किया गया था कि क्या चीनी नेताओं ने तिब्बत में हाल में हुई घटनाओं को लेकर चीन की तरफ से कोई चिंता जताई है। इस बारे में भारत के पक्ष की जानकारी देते हुए भारतीय अधिकारियों का कहना है कि तिब्बत के हालात पर भारत काफी सचेत रवैया अपना रहा है और इस बात पर जोर देना चाहता है कि तिब्बत को चीन का हिस्सा मानने के अपने पिछले रुख पर भारत अब भी कायम है। खबरों के अनुसार भारत ने इस बात पर भी जोर दिया है कि दलाई लामा एक सम्मानित अतिथि हैं और उनकी गतिविधियां राजनीतिक नहीं हैं। गौरतलब है कि तिब्बत में हाल के महीनों में 16 बौद्ध भिक्षु आत्मदाह का प्रयास कर चुके हैं और तिब्बत से सटे सिचुआन प्रांत में हाल में हुए हिंसक प्रदर्शनों में दो व्यक्ति मारे गए हैं। चीन ने मंगलवार को यह आरोप लगाया था कि हिंसा एवं आत्मदाह के लिए तिब्बती युवा कांग्रेस जिम्मेदार है। चीन ने हिंसा को बंद करने का अनुरोध किया है।

कृष्णा ने यहां एक करोड़ डॉलर की लागत से बने भारतीय दूतावास भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने अपने दिन की शुरुआत चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) के वरिष्ठ पोलित ब्यूरो सदस्य झू योंगकोंग से मुलाकात के साथ की।

पर्वतीय रेलवेः विभिन्न परियोजनाओं पर एक नजर

(ईटी ब्यूरो, 12 फरवरी)

भारतीयों के लिए पर्वतीय रेल मार्ग काफी रोमांस से जुड़े होते हैं। कई फिल्मों में दार्जिलिंग के ट्वाय ट्रेन या शिमला, ऊटी की ओर जाने वाले रेलमार्गों को दर्शाया गया है। भारतीय रेल ने भी इस धारणा को बदलने के लिए कुछ नहीं किया है। लेकिन अब उसे अपनी सोच बदलनी पड़ रही है और उसे पर्वतीय रेलवे को सामरिक और वाणिज्यिक लिहाज से देखना पड़ रहा है और इस बदलाव के पीछे चीन से मिल रही चुनौती है। इस बारे में भारतीय रेल अपनी नींद से तब जागा जब साल 2006 में चीन ने 1140 किलोमीटर लंबे क्विंघई–तिब्बत रेलमार्ग को चालू किया। चीन के रेलमार्ग अब भारतीय सीमा के लगातार करीब आते जा रहे हैं जिससे दिल्ली में सत्ता के गलियारों में चेतावनी की घंटी बजनी शुरू हो गई है। भारतीय राजनीतिक तंत्र यह स्वीकार कर चुका है कि सीमावर्ती इलाकों में रेलमार्ग न बनाने की उसकी दशकों पुरानी रणनीति नुकसानदेह साबित हो रही है। इसलिए अब हिमालय श्रेणी के सभी प्रमुख हिल स्टेशनों को छुट्टियों के गंतव्य से ज्यादा सामरिक चौकी के रूप में देखने के लिए कदम उठाया जा रहा है। ऐसा प्रस्ताव है कि उत्तराखंड के कर्णप्रयाग और अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर तक ट्रेन चलाई जाए। साल 2017 तक उत्तर–पूर्व के सभी राजधानियों को रेल से जोड़ने का लक्ष्य है। इन सभी नई पर्वतीय परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है, जिसका मतलब यह है कि इनके लिए पैसे की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। लेकिन एक तरफ चीन जहां अपनी परियोजनाओं को समय के भीतर पूरा कर रहा है, भारतीय परियोजनाएं अक्सर लक्ष्य समय तक पूरी नहीं होतीं। उदाहरण के लिए चीन के ल्हासा से शिगाजे तक बनने वाली 253 किलोमीटर लंबी रेलमार्ग की बात करें तो चार साल में बनने वाली इस परियोजना को 2014 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। इसके विपरीत आज़ाद भारत की पहली बड़ी पर्वतीय परियोजना 345 किलोमीटर लंबे जम्मू को बरामूला से जोड़ने वाले रेलमार्ग की बात करें तो एक राष्ट्रीय परियोजना होने के बावजूद यह तय समय से 10 साल पीछे है। अब इस परियोजना के साल 2017 तक ही पूरा हो पाने की उम्मीद है। कश्मीर परियोजना में देरी की वजह से भारतीय रेलवे को अपनी 4,295 करोड़ रुपए की ऋषिकेश परियोजना को पिछले साल अपनी पीएसयू शाखा रेल विकास निगम (आरवीएनएल) को सौंपना पड़ा। यह एक कठिन इंजीनियरिंग परियोजना है

जिसमें 81 सुरंग और 149 मोड़ हैं। भारतीय रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति इस प्रकार है:

कश्मीर रेलवे

जुड़ने वाले स्थानः जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला

लंबाईः 345 किलोमीटर

चुनौतियांः यह रेलमार्ग भूकंप संभावित क्षेत्रों और दुर्गम क्षेत्रों से होकर गुजरेगा

स्थितिः उधमपुर से काजीगुंड के बीच बचे हुए 173 किलोमीटर मार्ग पर निर्माण कार्य जारी है

पूरा होने का पूर्व निर्धारित समयः 2007

नया निर्धारित समयः 2017

शुरुआतः इस परियोजना की शुरुआत 1994 में हुई थी, लेकिन साल 2002 में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया जिसके बाद इसे नया जीवन मिला

सबसे लंबा सुरंग, सबसे ऊंचा पुलः

–इसके तहत बनने वाला 11 किलोमीटर लंबा पीर पंजाल रेलवे सुरंग भारत का सबसे लंबा और एशिया का दूसरा सबसे लंबा सुरंग होगा

–इसके तहत चिनाब नदी पर बनने वाला 1.3 किलोमीटर लंबा पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल होगा

रेलवे तीर्थ

ऋषिकेश एवं कर्णप्रयाग के बीच प्रस्तावित रेलमार्ग

लंबाईः 125 किलोमीटर

अनुमानित लागतः 4,295 करोड़ रुपए

सुरंगों की संख्याः 81

चुनौतियांः इस रेलमार्ग के रास्ते में उबड़–खाबड़ पहाड़ हैं जिनके आर–पार नदियां और घाटियां हैं

क्रियान्वयनः यह पहली पर्वतीय रेल परियोजना है जो सीधे भारतीय रेलवे द्वारा नहीं बल्कि उसके पीएसयू रेल विकास निगम द्वारा क्रियान्वित की जाएगी।

पूरा होने की तिथिः स्थान के अंतिम सर्वेक्षण के बाद यह तिथि निर्धारित की जाएगी।

चीन को जलवार्ता में शामिल करें: विशेषज्ञों

(आईएएनएस, 13 फरवरी, नई दिल्ली)

चीन द्वारा यारलुंग (ब्रह्मपुत्र जो तिब्बत से होकर आती है) नदी पर बहुत ज्यादा बांध बनाने और इस नदी की जलधारा को मोड़ने का चीनी इरादा सोमवार को यहां होने वाले एक सम्मेलन का मुख्य विषय रहा। सम्मेलन में शामिल कई विशेषज्ञों ने कहा कि इस मसले पर भारत सरकार को तत्काल चीन से वार्ता करनी चाहिए। तीन दिन के एशियाई सुरक्षा सम्मेलन के पहले दिन जल सुरक्षा पर आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए प्रतिरक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (आईडीएसए) के फेलो उत्तम कुमार सिन्हा ने कहा, "हमें इस बात के लिए बेहद सचेत रहना होगा कि हम अपनी राजनयिक नीति किस तरह से बनाते हैं। हमें उनको (चीन को) इस बात के लिए प्रतिबद्ध करना होगा कि वे सूचनाओं को साझा करें। हमें अपना पक्ष पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण से भी रखना होगा। सवाल यह समझने का है कि चीन क्या कर रहा है। हमें चीन को बातचीत की मेज पर लाकर यह समझना होगा कि आखिर वह क्या कर रहा है।" सत्र की अध्यक्षता कर रही सेवानिवृत्त राजनयिक लीला पूनप्पा ने कहा, "साफ तौर पर इस मसले पर लंबे समय तक पीछे पड़े रहना होगा।" कतर के जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय के विदेश सेवा विद्यालय (एसएफएस) में प्रोफेसर रॉबर्ट विरसिंग ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और चीन द्वारा उस नदी के मसले पर संयुक्त अध्ययन किया जाना चाहिए जिसे तिब्बत में यारलुंग और भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा, "चीन की योजना क्या है? सूचनाओं को साझा करने में आनाकानी से वह काफी बदनाम हो रहा है। जब तक संयुक्त अध्ययन नहीं होंगे तब तक हासिल जानकारियों को संदेह की नजरों से ही देखा जाएगा।"

इस मसले के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या करते हुए विरसिंग ने कहा कि चीन अब तक तिब्बत नदी पर 10 बांध बना चुका है। इसके अलावा 18 अन्य बांध निर्माण या योजना के विभिन्न चरणों में हैं। विरसिंग ने कहा, "इसके बाद अब वे ग्रेट बेंड (जहां से नदी भारत में प्रवेश करती है) पर नजरें गड़ाए हुए हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लंबा दर्रा है। यहां चीन तीन गॉर्ज (दुनिया की सबसे बड़ी यांगजे नदी पर बनी परियोजना) को भी बौना साबित कर देने वाली 38,000 मेगावॉट की जलविद्युत परियोजना लाने की तैयारी कर रहा है। चीन की यह भी योजना है कि ल्हासा की ओर से आने वाली 20 फीसदी नदियों को उत्तर की ओर मोड़ दिया जाए। इसका बांग्लादेश पर असर बहुत विध्वंसकारी हो सकता है। लेकिन इन सबसे चीन को निचली जलधाराओं पर 'व्यापक नियंत्रण' हासिल हो सकेगा। ग्रेट बेंड परियोजना के तहत बहते नदी पर बांध तैयार होगा और इसके भारत एवं बांग्लादेश पर पड़ने वाले जलविज्ञान प्रभाव को भूला नहीं जा सकता।" इससे भी व्यापक मसले पर बात करते हुए विरजिंग ने कहा कि दुनिया के 145 देशों में करीब 263 झील और नदियां हैं और पिछले 60 साल में इनके बारे में 37 'गहरे' विवाद हुए हैं, जबकि करीब 200 समझौतों और बंदोबस्त पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ध्यान दिलाया कि भारत–पाकिस्तान के बीच पिछले 60 साल से सिंधु जल समझौता कायम है, जबकि दोनों देशों के बीच दो बार कड़वी जंग भी हो चुकी है। विरजिंग का कहना था, "इस सबको देखते हुए द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय समझौतों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। करीब 30 साल के गहन बातचीत के बाद ही अंतरराष्ट्रीय जल धाराओं में नौपरिवहन के इस्तेमाल से संबंधित द्विपक्षीय समझौते पर 1997 में हस्ताक्षर हो सका।

चीन जब तिब्बत के ऊपरी हिस्सों में ब्रह्मपुत्र के जल के दोहन का प्रयास कर रहा है, भारत के लिए भी यह आवश्यक हो गया है कि अरुणाचल से होकर अन्य पड़ोसी देशों की ओर जाने वाली नदियों पर अपने पहले उपयोगकर्ता के अधिकार का इस्तेमाल करे।

इसके सुस्त अनुमोदन प्रक्रिया की वजह से केवल 24 देश ही इसको अनुमोदित कर पाए जो कि जरूरी 36 अनुमोदन का 60 फीसदी हिस्सा ही हैं। चीन ने इसके खिलाफ मत दिया था और 14 हिमालयी देशों में से किसी ने भी इसे अनुमोदित नहीं किया है। साफ है कि हमें कुछ और रास्ता निकालना होगा।

डेमवे परियोजना से भारत का पहले उपयोगकर्ता का अधिकार स्थापित होगा

(टीएनएन, फरवरी, गुवाहाटी)

भारतीय विशेषज्ञों के एक स्वतंत्र समूह की सख्त रिपोर्ट में यह चेतावनी दी गई है कि चीन एक 'बड़े सैन्य आक्रमण' के द्वारा भारतीय भौगोलिक क्षेत्र को हड़पने की कोशिश कर सकता है।

चीन जब तिब्बत के ऊपरी हिस्सों में ब्रह्मपुत्र के जल के दोहन का प्रयास कर रहा है, भारत के लिए भी यह आवश्यक हो गया है कि अरुणाचल से होकर अन्य पड़ोसी देशों की ओर जाने वाली नदियों पर अपने पहले उपयोगकर्ता के अधिकार का इस्तेमाल करे। यद्यपि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के लोहित नदी पर 1750 मेगावॉट के डेमवे लोअर जलविद्युत परियोजना को मंजूरी देते समय चीन का कोई उल्लेख नहीं किया है, लेकिन एक सूत्र का कहना है कि इसे मंजूरी देने में परियोजना के सामरिक महत्व का निस्संदेह ध्यान रखा गया है। पिछले साल दिसंबर में राष्ट्रीय वन्यजीवन बोर्ड की 24वीं स्थायी समिति की बैठक में अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सामरिक रूप से महत्वपूर्ण होने और विकास परियोजनाओं की मंजूरी में देरी से स्थानीय लोगों में निराशा का मसला उठाया था। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के निदेशक असद रहमानी के डेमवे के परियोजना स्थल जांच रिपोर्ट के जवाब में अरुणाचल सरकार ने तर्क दिया कि इस परियोजना से भारत को अपने पहले इस्तेमालकर्ता के अधिकार को स्थापित करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने राष्ट्रीय वन्यजीवन बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) के सदस्यों के विरोध के बावजूद मंगलवार को डेमवे परियोजना के लिए वन्यजीवन मंजूरी दे दी। एनबीडब्ल्यूएल के सदस्य इस परियोजना के पारिस्थितिकी और असम की निचली ध ाराओं के पास रहने वाले लोगों पर संभावित असर को लेकर विरोध कर रहे थे। रहमानी ने अपनी रिपोर्ट में इस परियोजन के जैवविविधता और असम के निचले हिस्सों, खासकर बांध के शुरू होने के बाद दिन–प्रतिदिन लोहित नदी में जल के प्रवाह पर पड़ने वाले असर पर गंभीर चिंता जताई थी। बांध विरोधी आंदोलनकारियों का कहना है कि डेमवे परियोजना को वन्यजीवन मंजूरी से इस इलाके में जंगलों के सफाए का रास्ता खुल गया है। एक बांध विरोधी आंदोलनकारी ने कहा, "एनबीडब्ल्यूएल सदस्यों द्वारा बांध के पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले असर के बारे में आशंका जताने के बावजूद इस परियोजना को वन्य मंजूरी दी जा रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।" कृषक मुक्ति संग्राम समिति (केएमएसएस) के महासचिव अखिल गोगोई ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने डेमवे परियोजना को मंजूरी देने में असम की निचली धाराओं के आसपास रहने वाले लोगों को नजरअंदाज कर दिया है।

'भारत अपने आंतरिक मामलों में चीन की दखल बर्दाश्त नहीं करेगा'

(फायूल डॉट कॉम, धर्मशाला, 27 फरवरी)

भारतीय रक्षा मंत्री ए.के.एंटोनी के उत्तर–पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में दौरे का विरोध करने वाले चीन के बयान पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते अरुणाचल प्रदेश राज्य के गठन की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर वहां रक्षामंत्री एंटनी के दौरे के बाद चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता होंग लेई ने शनिवार को कहा था कि भारत को ऐसा कोई कदम उठाने से बचना चाहिए जिससे सीमा विवाद और 'उलझे' और चीन ने भारत से कहा कि वह 'सीमावर्ती इलाकों में शांति एवं स्थिरता को बनाए रखे।' चीन की आपत्तियों पर प्रतिक्रिया जताते हुए भारतीय विदेश मंत्री एस. एम. कृष्णा ने शनिवार को पत्रकारों को बताया कि भारत इस 'गंभीर' मसले को चीन के सामने एक उपयुक्त मंच पर उठाएगा और उन्होंने जोर देकर कहा कि "भारत अपने आंतरिक क्षेत्रीय मामलों में चीन के दखल को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत के उत्तर–पूर्वी इलाके में स्थित सभी सात राज्य भारत और भारतीय भूखंड का अभिन्न हिस्सा हैं और चीन को एंटोनी के अरुणाचल प्रदेश दौरे पर विपरीत टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है।"

रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी ने अरुणाचल प्रदेश में उनके दौरे पर चीन की आपत्ति को लेकर 'आश्चर्य' जाहिर किया है। रक्षा मंत्री ने कहा, "मुझे यह प्रतिक्रिया सुनकर काफी आश्चर्य हुआ है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और वास्तव में आपत्तिजनक है।" उन्होंने कहा, "मेरा यह अधिकार और कर्तव्य है कि देश के किसी भी इलाके का दौरा करूं। मैंने साल 1984 से ही अब तक अरुणाचल प्रदेश का कई बार दौरा किया है और मुझे यह देखकर खुशी होती है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य अच्छी प्रगति कर रहा है। चीन लगातार समूचे अरुणाचल प्रदेश को अपना भौगोलिक क्षेत्र बताता रहा है और वह अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों को वीजा देने से इनकार करता है। इस बीच, लद्दाख स्थित एक सामाजिक संगठन ने दावा किया है कि चीन लगातार भारत–तिब्बत सीमा के पार अपनी स्थिति मजबूत करता जा रहा है और वह देमचोक में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के नजदीक अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में संपर्क बढ़ा रहा है। एक ब्रिटिश समाचारपत्र ने पिछले महीने यह खबर दी थी कि नई दिल्ली में जनवरी के मध्य में हुई 15वें दौर की भारत–चीन विशेष प्रतिनिधि वार्ता गतिरोध के साथ समाप्त हुई थी क्योंकि चीन इस बात पर अड़ गया था कि वह 'अरुणाचल प्रदेश का अपना हिस्सा' लेने से कम पर बात नहीं मानेगा। 15वें दौर की वार्ता की चर्चा करते हुए सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च नई दिल्ली के

वरिष्ठ फेलो सी. राजामोहन ने कहा कि भारत एवं चीन के बीच सीमा विवाद में 'तिब्बत का मसला विकट रूप से गुंथा हुआ है।"

इंडियन एक्सप्रेस में पिछले महीने लिखे एक आलेख में राजा ने कहा, "इस मसले पर काफी संवेदनशीलता को देखते हुए भारत एवं चीन यह समझते हैं कि क्षेत्रीय विवाद में तिब्बत का मसला विकट रूप से गुंथा हुआ है।" उन्होंने कहा, "तिब्बत मसले पर शांतिपूर्ण रूप से भारत–चीन वार्ता की शुरुआत और तिब्बती सीमा पर सकारात्मक रूप से संपर्क बढ़ाना भारत एवं चीन के लिए व्यावहारिक समझ की बात होगी।" भारत और चीन अधिकृत तिब्बत करीब 3488 किलोमीटर लंबी सीमा को साझा करते हैं जिस पर विवाद है। इस विवादित सीमा की वजह से साल 1962 में छोटा लेकिन रक्तरंजित युद्ध हुआ। इसके बाद से ही दोनों एशियाई महाशक्तियों के बीच सैन्य संबंध सहज नहीं हैं और कई दौर की सीमा वार्ता का कोई खास नतीजा नहीं निकला है।

भारतीय विशेषज्ञों ने चीन की तरफ से 'बड़े सैन्य आक्रमण' की चेतावनी दी

(फायूल डॉट कॉम, धर्मशाला, 29 फरवरी)

भारतीय विशेषज्ञों के एक स्वतंत्र समूह की सख्त रिपोर्ट में यह चेतावनी दी गई है कि चीन एक 'बड़े सैन्य आक्रमण' के द्वारा भारतीय भौगोलिक क्षेत्र को हड़पने की कोशिश कर सकता है। 'गुटनिरपेक्ष 2: 21वीं सदी के लिए विदेश और सामरिक नीति' शीर्षक के रिपोर्ट में कहा गया है कि, "कुछ सालों से चीन के साथ हमारी सीमा पर ज्यादातर समय स्थिरता रही है। लेकिन चीन ताकत के बल पर अपने भौगोलिक क्षेत्र दावे (खासकर अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में) को साकार करने की कोशिश कर सकता है।" इस रिपोर्ट में यह तर्क दिया गया है कि भारत पूरी तरह से "अरुणाचल प्रदेश या लद्दाख में एक बड़े सैन्य आक्रमण की आशंका को खारिज नहीं कर सकता।" रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि भारत को 'जैसे को तैसा' रणनीति अपनाकर इसका प्रतिकार करना होगा।

मंगलवार को नई दिल्ली में इस रिपोर्ट को जारी करने के मौके पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन और उनके दो पूर्ववर्ती अधिकारी एम.के. नारायणन और ब्रजेश मिश्रा मौजूद थे। रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए ब्रजेश मिश्र ने चीन को एक 'दुश्मन देश' बताया जो लगातार भारत को दक्षिण एशिया में सीमित रखने के लिए पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। मिश्रा ने कहा, "चीन यह जानता है कि जब तक भारत को दक्षिण एशिया में उलझाए रखा जाता है वह दक्षिण–पूर्व एशिया या वैश्विक स्तर पर बड़ी भूमिका नहीं निभा पाएगा।"

रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन लगातार भारत की विदेशी नीति और सुरक्षा के लिए "एक बड़ी चुनौती'' बना हुआ है और यह सुझाव दिया गया है कि सैन्य आक्रमण की स्थिति में भारत को भी जैसे को तैसा की रणनीति अपनाते हुए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ऐसी ही कार्रवाई करनी होगी।

रिपोर्ट में कहा गया है, "चीन एक ऐसी बड़ी ताकत है जो सीधे भारत की भू–भौगोलिक जमीन पर अतिक्रण कर रहा है। जैसे–जैसे उसकी आर्थिक एवं सैन्य क्षमता बढ़ती जाएगी भारत के मुकाबले उसकी ताकत का और विस्तार होता जाएगा।" रिपोर्ट में कहा गया है यदि "चीन जमीन हड़पने की कार्रवाई करता है तो भारत को रक्षात्मक एवं आक्रामक क्षमता के समिश्रण जैसी नीति अपनानी होगी।" रिपोर्ट में यह सुझाव भी दिया गया है कि भारत को चीन द्वारा कब्जाए गए क्षेत्रों में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए तैयार रहना होगा और तिब्बत में विकसित परिवहन एवं सैन्य ढांचे के जवाब में अपनी क्षमताओं का विकास करना होगा। पिछले साल दिसंबर में चीन के राष्ट्रपति हू जिनताओ ने अपनी नौसेना से कहा था कि वे 'आधुनिकीकरण को तेज करें और युद्ध के लिए तैयार रहें।" इस साल की शुरुआत में एक वैश्विक रिसर्च समूह आईएचएस ने अपनी रिपोर्ट में अनुमान लगाया था कि चीन का सैन्य खर्च साल 2011 के 119.8 अरब डॉलर के मुकाबले साल 2015 तक बढ़कर 238.2 अरब डॉलर तक हो जाएगा और इसकी वजह से जापान एवं भारत जैसे इस क्षेत्र के 12 महत्वपूर्ण प्रतिरक्षा बाजारों का कुल सैन्य खर्च भी काफी बढ़ जाएगा। यह रिपोर्ट चीन के विदेश मंत्री यांग जिची के दो दिवसीय भारत दौरे के आसपास ही जारी हुई है। जिची विदेश मंत्री स्तर की वार्षिक वार्ता में हिस्सा लेने के लिए भारत आए थे। इस रिपोर्ट को तैयार करने वाले प्रमुख विश्लेषकों में भारत के पूर्व विदेश सचिव श्याम सरण, नंदन नीलेकणि, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सैन्य सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) प्रकाश मेनन, किंग्स कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर सुनील खिलनानी, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के अध्यक्ष प्रताप भानु मेहता, फिक्की के महासचिव राजीव कुमार, सीपीआर के सीनियर फेलो श्रीनाथ राघवन और द हिंदू के संपादक सिद्धार्थ वरदराजन शामिल हैं।

अमेरिका के मस्केटाइन शहर के व्यापारिक इलाके में जहां जगह–जगह अवरोध खड़े किए गए हैं वहां चीन की नीतियों, खासकर तिब्बत के प्रति नीतियों को लेकर भारी प्रदर्शन हुए हैं।

तिब्बत के हालात पर तिब्बती संसद ने दिखाई एकजुटता

(तिब्बत डॉट नेट, धर्मशाला)

निर्वासित तिब्बती संसद ने एक बयान जारी कर तिब्बत के भीतर नाबा, ताउ, चामदो, कार्जे, गोलोग दाराग और अन्य तिब्बती इलाकों में हाल में चीनी सुरक्षा बलों के भारी दमन से पीड़ित लोगों के प्रति अपनी एकजुटता दिखाई है। तिब्बती संसद के एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली स्थित कई विदेशी दूतावासों का दौरा किया। उन्होंने राजदूतों को तिब्बत के भीतर के गंभीर हालात की जानकारी दी और उनसे निवेदन किया कि वे अपने देश की संसद से कहें कि वे तत्काल चीन सरकार के

"मेरे दिल में कुछ है। हम अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं।"

चीन सरकार और उसकी मीडिया ने कुछ आत्मदाह की घटनाओं की पुष्टि की है और अन्य घटनाओं का खंडन किया है।

पास एक प्रतिनिधिमंडल भेजें। तिब्बती संसद ने तिब्बतियों से भी यह निवदेन किया कि वे तिब्बत में अपने प्राणों का बलिदान कर देने वाले लोगों के प्रति सम्मान और एकजुटता प्रकट करने के लिए 22 फरवरी को नए साल का उत्सव न मनाएं।

संसद द्वारा जारी बयान में कहा गया है, "हमने तिब्बतियों से कहा है कि वे 22 फरवरी को आने वाले नए साल का उत्सव न मनाएं। हम हर किसी से निवेदन करते हैं कि आत्मदाह और बर्बर चीनी कदमों से अपनी जान गवां देने वाले सभी लोगों की आत्मा के लिए प्रार्थना करें। तिब्बत में रहने वाले तिब्बतियों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए नए साल के पहले दिन धर्मशाला स्थित तिब्बती संसद का हर सदस्य सायं 5 बजे तक व्रत रखेगा।"

गौरतलब है कि पिछले साल 16 मार्च से अब तक चीन सरकार के विरोध में 16 तिब्बती आत्मदाह का प्रयास कर चुके हैं। इसमें 12 तिब्बती शहीद हो गए हैं, जबकि बाकी की हालत के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। साल 2009 में भी कीर्ति मठ के एक भिक्षु तापे ने चीन सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ खुद को आग लगा ली थी और तब से उनका कुछ पता नहीं है।

जी की यात्राः पुलिस ने लगाए अवरोध

जब एक एसयूवी वहां पहुंचा जिसकी अगली सीट पर एक चीनी व्यक्ति बैठा था तो उसे बिना किसी पूछताछ के जाने दिया गया, इसी एसयूवी के पिछले हिस्से में मैकक्लैची का रिपोर्टर छुपा हुआ था।

(क्विकटाइम्स डॉट कॉम, 15 फरवरी, मस्केटाइन)

अमेरिका के मस्केटाइन शहर के व्यापारिक इलाके में जहां जगह–जगह अवरोध खड़े किए गए हैं वहां चीन की नीतियों, खासकर तिब्बत के प्रति नीतियों को लेकर भारी प्रदर्शन हुए हैं। इसी अवरोध के सामने एक जगह पर चीन के उप राष्ट्रपति जी जिनपिंग, लोवांस से मिले हैं जिनसे उनकी दोस्ती की शुरुआत 27 साल पहले हो चुकी थी। अवरोध के पार प्रदर्शनकारी जोर–जोर से नारे लगा रहे थे। ज्यादातर राज्य के बाहर से आए प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे थे–'चीन झूठ बोल रहा है, तिब्बती मर रहे हैं।' कुछ प्रदर्शनकारी चिल्ला रहे थे–शर्म करो जी जिनपिंग। लोवा शहर से दो बसों में भरकर यहां पहुंचे चीन समर्थक प्रदर्शनकारी भी जगह–जगह दिख रहे हैं। वे नारे लगा रहे हैं–'एक चीन', 'तिब्बत चीन का हिस्सा है।' करीब 100 की संख्या में आए ज्यादातर हान चीनी लोगों का यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। पुलिस इन लोगों को केवल यह चेतावनी दे रही थी कि वे सड़क को जाम न करें। यह साफ नहीं हो पाया है कि जी ने विरोध प्रदर्शन करने वालों पर गौर किया या नहीं। लेकिन रोजर और सारा लैंडे के घर में वह कार से पहुंचे जिससे व्यावहारिक रूप से यह संभव नहीं था कि वे नारे लगाते और तख्तियां लिए हुए लोगों को नजरअंदाज कर पाए हों। इसके पहले फर वृक्ष से भरी दूसरी सड़क का कोना शांत था क्योंकि चीन समर्थक प्रदर्शनकारियों की संख्या उन महिला प्रदर्शनकारियों से ज्यादा थी जो चीन में एक आध्यात्मिक पंथ फालुन गोंग पर प्रतिबंध का विरोध करने वाली तख्तियां लिए हुई थीं। जब इन महिलाओं ने अपनी तख्तियां मीडिया को दिखाने की कोशिश की तो चीन समर्थक प्रदर्शनकारी बार–बार चालबाजी कर उनके सामने आते रहे ताकि उनकी तख्तियां मीडिया वालों को न दिख सकें। इसके बाद तिब्बत की आज़ादी की मांग करने वाले प्रदर्शनकारियों का भी एक समूह आ गया और विरोध प्रदर्शन की आवाज़ काफी तेज हो गई। मिनियापोलिस के तेनजिन पसांग ने कहा,"हम दुनिया भर का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।"तिब्बत 1950 के दशक से ही चीन के नियंत्रण में है। चीन सरकार का कहना है कि तिब्बत शताब्दियों से उसका हिस्सा रहा है। तिब्बती प्रदर्शनकारी आज़ादी की मांग कर रहे हैं, इन प्रदर्शनकारियों ने यह आरोप भी लगाया है कि चीन सरकार हत्याएं और दमन कर रही है। पसांग ने बताया कि उनके मां–बाप साल 1959 में ही भागकर भारत आ गए थे और पसांग का जन्म भारत में ही हुआ। लेकिन वे तिब्बत को भूले नहीं हैं। उन्होंने कहा, "मेरे दिल में कुछ है। हम अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं।" एक जगह पर तो कुछ तिब्बती प्रदर्शनकारी पीछे की तरफ घुसपैठ करने में सफल रहे और चुस्त सुरक्षा व्यवस्था को भेदकर लैंडे के निवास तक पहुंच गए। लेकिन सुरक्षा बलों ने तत्काल उन्हें धकेलकर इस इलाके से बाहर कर दिया। सड़क पर चीन की एकता का आह्वान करने वाले प्रदर्शनकारियों के साथ लोवा विश्वविद्यालय के प्रयोगशाला शोधकर्ता दिंग वु भी शामिल हुए। उनका कहना है कि चीन काफी विविधता वाला है और उसकी अपनी समस्याएं हैं। लेकिन उन्होंने कहा, "हम अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा।"

तिब्बत समर्थक प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि चीन के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले लोगों को वहां की सरकार से फायदा मिला है। दोनों पक्षों ने एक–दूसरे पर प्रदर्शन के लिए पैसा पाने का आरोप लगाया। सड़क के किनारे कई अमेरिकी प्रदर्शनकारी और कई जिज्ञासु स्थानीय निवासी भी थे जो वहां खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। डेवेनपोर्ट की काथी केली ने एक तख्ती ली थी जिस पर लिखा हुआ था, "अमेरिका आज़ादी के पक्ष में खड़ा है। " उन्होंने इस बात पर आपत्ति की अमेरिकी सरकार जी का स्वागत कर रही है। उन्होंने कहा, "वह बिल्कुल इसके विपरीत खड़े होते हैं जिसके लिए अमेरिकी सरकार खड़ी होती है।" उन्होंने इस बात की भी शिकायत की चीनी लोग अमेरिकियों की नौकरियां छीन रहे हैं।

आंतरिक इलाकों में एक पत्रकार के दुर्लभ दौरे से तिब्बत में चीनी दमन का खुलासा

टाम लैसेटर*(मैकक्लैची न्यूजपेपर्स,15 फरवरी,अबा, चीन)*

भिक्षु ने अपने लाल लबादे में हाथ डाला, एक छोटा

नोटबुक निकाला और उसमें से धीरे से सरकते हुए एक छोटी तस्वीर बाहर आ गई। सिलवटों वाली तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति उनका रिश्तेदार था। भिक्षु ने बताया कि वह भी अबा कस्बे के बाहरी इलाके में स्थित बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बने एक मठ में भिक्षु थे। लेकिन एक चीनी अधिकारी ने उनकी हत्या कर दी। यह एक ऐसी दुःखद घटना है जिसके बारे वे सार्वजनिक तौर पर चर्चा भी नहीं कर सकते। भिक्षुओं ने बताया कि स्थानीय सरकार का एक 'कामकाजी दल' अक्सर मठ के दौरे पर आता है और असंतोष की हवाओं को सूंघने का प्रयास करता है। उन्होंने बताया कि अक्सर ऐसा होता है कि जब वे प्रार्थना या अध्ययन के बाद अपने आवास कक्षों में आते हैं तो देखते हैं कि दरवाजे खुले हुए हैं और तलाशी की वजह से कमरे में सामान बिखरा पड़ा है। भिक्षुओं ने तस्वीरें दिखाकर यह समझाने की कोशिश की कि आखिर क्यों तिब्बती समुदाय के लोग (ज्यादातर भिक्षु या पूर्व भिक्षु) अबा और आसपास के इलाकों में चीनी शासन के खिलाफ विरोध के लिए अपूर्व कदम उठाते हुए आत्मदाह कर रहे हैं। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक मार्च, 2011 से अब तक 20 से 23 तिब्बतियों ने आत्मदाह किया है जिसमें कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है। करीब 40 साल के भिक्षु इस खबर के लिए हर तिब्बती से बात कराने को तैयार दिखे, इस शर्त पर कि उनका नाम नहीं दिया जाएगा और कुछ अन्य पहचान भी छिपाए जाएंगे क्योंकि उन्हें पुलिस द्वारा पकड़े जाने का डर था। उन्होंने कहा, "हमारी नजरों में चीन न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण नहीं है। हमारे दिलों में काफी पीड़ा है और जब हम इसे लंबे समय तक सहन नहीं कर पाते तो खुद को आग लगाकर मौत को गले लगा लेते हैं।

संबन्धित : चीन में भी तिब्बत के प्रति सहानुभुति

चीन सरकार और उसकी मीडिया ने कुछ आत्मदाह की घटनाओं की पुष्टि की है और अन्य घटनाओं का खंडन किया है। हालांकि, सरकार इस इलाके में बाहरी लोगों का प्रवेश रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पुलिस अक्सर सड़कों को अवरुद्ध कर देती है, वाहनों की तलाशी लेती है और विदेशियों, खासकर पत्रकारों को वापस भेज देती है। पिछले हफ्ते मैकक्लैची का पत्रकार किसी अमेरिकी समाचार संगठन का ऐसा पहला पत्रकार बन गया जो मार्च में आत्मदाह का सिलसिला शुरू होने के बाद अबा पहुंचा हो। ऐसा करने के लिए यह रिपोर्टर गाड़ी के पिछले हिस्से में फर्श पर लेटकर गया और उसके ऊपर दो बड़े बैग और एक स्लीपिंग बैग रखकर उसे ढंक दिया गया था। इस तरह वह कई जांच चौकियों से गुजरते हुए चीनी सुरक्षा बलों को चकमा देने में कामयाब रहा। चीन काफी समय से यह आरोप लगाता रहा है कि तिब्बती इलाकों में अशांति दलाई लामा के षडयंत्रों के कारण है। दलाई लामा तिब्बतियों के आध्यात्मिक गुरू हैं जो साल 1959 में चीनी शासन के खिलाफ एक जनक्रांति के विफल हो जाने के बाद जान बचाकर भारत चले गए थे। लेकिन सिचुआन प्रांत में जहां कि आत्मदाह की ज्यादातर घटनाएं हुई हैं स्थानीय तिब्बतियों से बात करने से पता चलता है कि असंतोष को दबाने के लिए चीन जिस तरह की दबंग नीतियों का इस्तेमाल कर रहा है उससे अशांति और भड़क रही है। चीन के उपराष्ट्रपति और संभावित अगले राष्ट्रपति जी जिनपिंग इस सप्ताह अमेरिका के दौरे पर हैं और बेहतर समझ की बातें कर रहे हैं, इस बीच उनकी सरकार देश में तिब्बतियों की भूमि को अपने सशस्त्र सैनिकों की बाढ़ से रौंद रही है। पिछले सप्ताह अबा के प्रवेश बिंदु पर बने एक जांच चौकी पर कम से कम सात पुलिस कर्मी तैनात थे। जब एक एसयूवी वहां पहुंचा जिसकी अगली सीट पर एक चीनी व्यक्ति बैठा था तो उसे बिना किसी पूछताछ के जाने दिया गया, इसी एसयूवी के पिछले हिस्से में मैकक्लैची का रिपोर्टर छुपा हुआ था।

जांच के दायरे में तिब्बती

तिब्बती समुदाय के लोगों को कड़ी जांच का सामना करना पड़ता है। पड़ोस के गांव के एक तिब्बती ने बताया कि जब वह अबा (जिसे तिब्बती में नाबा कहते हैं) में प्रवेश कर रहा था तो उसके टैक्सी के आंतरिक हिस्से का पूरी तरह से चीर–फाड़ कर दिया गया। जिस दिन पत्रकार अबा पहुंचा उसी दिन कस्बे के बाहरी इलाके में स्थित ननरी की एक 18 साल की भिक्षुणी ने आत्मदाह कर लिया था। खबरों के आग अनुसार शरीर में आग लगाने के बाद तिब्बती भिक्षुणी तेनजिन छोदोन चीन सरकार के खिलाफ नारे लगा रही थीं। तिब्बती बौद्ध मठों के लिए प्रसिद्ध इस कस्बे के कई हिस्सों को सैनिक छावनियों में तब्दील कर दिया गया है। प्रवेश बिंदु के बाद बने कुछ अवरोधों के बाद शॉटगन और असाल्ट राइफल्स लिए अर्द्धसैनिक बलों के जवान तैनात हैं। सुरक्षा बलों को ढोने वाले तीन बड़े ट्रक सड़क के किनारे खड़े हैं और इनमें बंदूके लिए और सुरक्षाकर्मी बैठे हैं। थोड़ा और ऊपर जाने पर यातायात को कई और दंगा अवरोध से गुजरना पड़ता है और सुरक्षा बलों ने जिस तरह से पोजीशन ली है वह ऐसे ही है जैसे आतंकवादियों से निपटने के लिए किया जाता है। अबा में सुरक्षा व्यवस्था इतनी घनी है कि किसी भिक्षु या किसी से भी बात करना असंभव है क्योंकि उन लोगों के खतरे में पड़ने का जोखिम था जिनसे पत्रकार बात करता। इंटरनेट पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी और अबा से टेक्स्ट मैसेज भेजने का प्रयास भी बार–बार विफल हो रहा था। यहां से सैकड़ों मील दूर शहर चेंगदू के बाहरी इलाके से ही पुलिस के अवरोध और गश्ती दल दिखने शुरू हो गए थे। यहां तक कि अच्छी तरह फैले हुए मेट्रो शहर चेंगदू के प्रमुख तिब्बती इलाकों में भी धूपबत्ती व धार्मिक सामग्री बेचनी वाली दुकानों और रेस्त्रां के बाहर पहरेदारी के लिए हर तरफ पुलिसकर्मी दिख रहे थे।

उसके ऊपर का शीशा चटक गया है उसमें से एक टुकड़ा गायब भी है, लेकिन इंद्रधनुष के रंग का फ्रेम और तस्वीर पूरी तरह सुरक्षित है।सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी तलाशी और जेल में रहने के उन भिक्षु के रिकॉर्ड को देखते हुए ऐसी तस्वीर आसपास रखना उनके लिए खतरनाक हो सकता था, इसलिए वह उसे दूर ले गए।

इसके पहले नवंबर में भी मैकक्लैची के एक रिपोर्टर ने अबा पहुंचने का प्रयास किया था लेकिन वह पकड़ा गया और चीनी पुलिस ने करीब दो घंटे की पूछताछ के बाद उसे बीजिंग जाने का आदेश देकर छोड़ दिया। ऊंचे पहाड़ों और धुंध के बीच स्थित अबा तिब्बती अशांति के केंद्र के रूप में अंतरराष्ट्रीय चर्चा में तब आया था जब पिछले साल मार्च में यहां स्थित कीर्ति मठ के एक भिक्षु ने आत्मदाह कर लिया था। खबरों के अनुसार उसने साल 2008 के विरोध प्रदर्शनों की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर ऐसा किया था। अबा सहित समूचे तिब्बती पठार में साल 2008 में हुए विरोध प्रदर्शनों और दंगों में बड़े पैमाने पर खून–खराबा हुआ था। खबरों के अनुसार आत्मदाह की घटना के बाद करीब 300 भिक्षुओं को ट्रकों में भर दूर अज्ञात स्थानों पर ले जाया गया जिस पर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई थी। चीनी अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने तिब्बत (जो उनके हिसाब से स्वायत्त क्षेत्र है) और उसके पास के सिचुआन जैसे इलाकों में अस्पतालों, सड़कों और स्कूलों के निर्माण पर अरबों डॉलर खर्च किए हैं। जैसा कि अबा से करीब 20 मील की दूरी पर लगा हरे मैदानों और नीले जल को वर्णित करता एक बोर्ड कहता है, "एकसाथ एक सभ्य और नए अबा का निर्माण।" कई तिब्बती सरकारी परियोजनाओं के फायदे को स्वीकार भी करते हैं। लेकिन वे उनकी संस्कृति और धार्मिक परंपराओं के स्वतंत्रता से पालन पर लगे सरकारी प्रतिबंधों से काफी नाराज हैं और दलाई लामा से दूर कर दिए जाने को लेकर भी वे गुस्सा प्रकट करते हैं। एक तिब्बती कहते हैं, "हम यह नहीं समझ पा रहे कि इस हालात के बारे में क्या कहा जाए।" उनके दरवाजे पर हमेशा दिखने वाली पुलिस रूपी खतरे ने तिब्बतियों के हालात को और जटिल बना दिया है। होंगयुंग (जो कि अबा से पूर्व में 65 या उससे कुछ ज्यादा दूरी पर पड़ता है) के 26 वर्षीय व्यापारी ने कहा, "यदि आप यह कहते हैं कि सरकार अच्छा रवैया नहीं अपना रही है तो यह पूरी तरह सही नहीं है। वे हमें कई अच्छी चीजें दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस काफी बुरा बर्ताव कर रही है। हम कुछ नहीं समझ पा रहे कि इस हालात के बारे में क्या कहा जाए।" भूरे लेदर कोट पहने और चश्मा लगाए इस व्यक्ति ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, "आपको अबा में किसी से बात करनी चाहिए।" परिवार के लिविंग रूम में एक बल्ब की रोशनी में बैठे उनके छोटे भाई ने कहा, "निश्चित रूप से चीजें अच्छी नहीं हैं, वे लोगों की हत्याएं कर रहे हैं।" इसके बाद दोनों भाई करीब पचास साल के अपने पिता की ओर मुखातिब हुए जो अपने कंधे पर हरा सा दिखने वाला जैकेट लटकाए हुए थे और उनके हाथ में एक सिगरेट था।

तिब्बती आत्मदाह क्यों कर रहे हैं?

पिता पहले ही इस बात को साफ कर देना चाहते थे कि वह जो कुछ भी कहेंगे उसकी 'कानूनी जवाबदेही उनकी नहीं होगी।' उन्होंने कहा, "चीन सरकार ने यह संदेश जारी किया है कि यह सब चीजें विदेशी साजिश के तहत हो रही हैं, लेकिन निश्चित रूप से खुद को आग लगा लेने वाले लोग स्थानीय हैं।" इसके बाद पिता चुप हो गए और अपने सामने जलते छोटे चूल्हे की ओर देखने लगे जो याक के गोबर से बने उपले को जलाकर कमरे को गरम कर रहा था।

एक बड़े शहर में जाने की तैयारी कर रहे करीब 20 साल के छोटे भाई ने एक ऐसे दावे से बात खत्म की जिसको कोई काट नहीं सकता था। उसने कहा, "लोग खुद को आग लगा रहे हैं क्योंकि वे पीड़ित हैं या उनके परिवार के किसी सदस्य की सरकार ने हत्या की है और अब वे घृणा से भरे हुए हैं। वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपने दर्द और कठिनाई को व्यक्त करना चाहते हैं।" इस इलाके में रहने वाले ज्यादातर तिब्बतियों से जब रिपोर्टर ने संपर्क किया तो उनका कहना था कि वे इन मसलों पर बात नहीं करना चाहते।

अबा से पूर्व करीब 30 मील दूर स्थित चाली कस्बे के पास रहने वाले एक चरवाहे ने संकेत से रिपोर्टर को अपने मकान के भीतर आने को कहा। घर के भीतर पहुंच जाने पर 67 साल के इस सख्त और मोटे हाथ वाले व्यक्ति ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, "मुझे माफ करना, मुझे माफ करना, मैं इस सब पर बात करने का साहस नहीं कर सकता।" भूरे सूती कपड़े वाले पैंट और गहरे रंग का जाड़े वाला जैकेट पहने इस चरवाहे ने बाहर आकर खेतों से गुजरते हुए सलाह दीः भिक्षुओं से बात करो, वे क्या कह रहे हैं। एक भिक्षु ने जिनके रिश्तेदार की मौत हो गई थी, मार्च 2008 के हंगामे के दौरान चीन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। भिक्षु ने बताया कि इसके बाद जब पुलिस आई तो उसने मठ को घेर लिया और धमकी दी कि यदि इस घटना में शामिल लोग खुद सामने नहीं आते तो उनके मठ को नष्ट कर दिया जाएगा। उसकी गिरफ्तारी के लिए जारी आधिकारिक दस्तावेजों में कहा गया था कि वह और अन्य लोग एक ऐसे कृत्य में शामिल हुए हैं जिससे "लोक व्यवस्था भंग हुई है और यातायात जाम हुआ है।" ट्रक में एक प्लास्टिक बैग में भरकर लाए गए कागजात को भिक्षुओं ने रख लिया, जबकि वे मंदारिन भाषा में थे जिसे तिब्बती भिक्षु अच्छी तरह से नहीं समझ सकते थे। भिक्षु ने कहा कि उन्हें जेल में बंद कर दिया गया और खाने को इतनी मामूली मात्रा में दलिया दिया जाता था कि उनके लिए खड़ा होना भी मुश्किल लग रहा था। इसके बाद उन्हें श्रम–सुधार शिविर में भेजा गया। करीब दो साल के जेल के अनुभवों को बताने से हिचक रहे भिक्षु ने कहा, "उन्होंने मुझे बताया कि दलाई समूह हमारे देश की शांति यात्रा का रोड़ा है।" लेकिन उनके रिश्तेदार कभी वापस नहीं आए। उस भिक्षु एवं मठ के अन्य भिक्षुओं ने बताया कि गिरफ्तार भिक्षु की सिर में पिटाई और इसके बाद सही उपचार न मिलने से जेल में ही मौत हो गई। इसके बाद दूसरे भिक्षु साल 2010 में अबा के पास वाले इलाके में लौट आए। यहां उनके जाने के बाद से अब तक हालात काफी बदल गए थे। हालांकि, याक के मक्खन से बनी मोमबत्तियां अब भी रात में जलती थीं। नए–नए सिर मुड़ाने वाले युवा भिक्षु तेजी से पहाड़ों पर चढ़ते–उतरते देखे जा सकते थे। भिक्षु ने यह देखा कि एक छुपी हुई जगह पर उनके द्वारा लगाई गई दलाई लामा की फ्रेमवाली तस्वीर अब भी वहीं है। उसके ऊपर का शीशा चटक गया है उसमें से एक टुकड़ा गायब भी है, लेकिन इंद्रधनुष के रंग का फ्रेम और तस्वीर पूरी तरह सुरक्षित है। सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी तलाशी और जेल में रहने के उन भिक्षु के रिकॉर्ड को देखते हुए ऐसी तस्वीर आसपास रखना उनके लिए खतरनाक हो सकता था, इसलिए वह उसे दूर ले गए।